to be set up in Mr. Narayanan's honour at Uzhavoor. I request the hon. Prime Minister and the Government to take urgent action to erect a statue of Shri K.R. Narayanan in New Delhi and to set up the educational institutions mentioned above in Uzhavoor division in Kottayam district, Kerala at the earliest.

(xvi) Need to set up Chambal Water Commission for distributing water of Chambal river between Madhya Pradesh and Rajasthan

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के मुरैना-श्योपुर एवं भिण्ड जिले को चम्बल नहर से पानी मिलता है जिससे लाखों किसान अपने खेतों को सिंचित करते हैं, परन्तु म.प्र. के हिस्से का 3900 क्यूसिक पानी समय पर नहीं मिलने से किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तथा राजस्थान सरकार पानी समय पर नहीं देती है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पानी बटवारे का निराकरण हो तथा चम्बल आयोग का गठन किया जाये।

14.28 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(i) Serial Bomb Blasts In Delhi
(ii) Terrorist Violence In Jammu And Kashmir
(iii) Naxalite attacks In Jehanabad, Bihar on 13.11.2005
and
(iv) Naxalite Attack at Home Guard Training Centre, Giridih, Jharkhand on 11.11.2005

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, I have an announcement to make.

The House would now take up discussion under rule 193, as listed. Shri Ajoy Chakraborty was to initiate the discussion. However, Prof. Vijay Kumar Malhotra has requested the hon. Speaker that he might be allowed to initiate the discussion. Hon. Speaker has expressed his thanks that Shri Ajoy Chakraborty has kindly consented to allow Prof. Malhotra to initiate the discussion. Shri Ajoy Chakraborty would be called to speak after Prof. Malhotra.

Prof. Vijay Kumar Malhotra may now initiate the discussion.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आंतरिक सुरक्षा पर इस सदन में चर्चा करने जा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिल्ली में हुये बम बलास्ट, श्रीनगर में हुये बम विस्फोट और जहानाबाद में माओवादियों तथा नक्सलवादियों द्वारा की गई हिंसा से संबंधित तीनों विषयों एवं अन्य कई विषयों पर इस सदन में वक्तव्य दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन जो वक्तव्य दिया, वह चाहे दिल्ली में हुये बम बलास्ट के बारे में हो, चाहे श्रीनगर में होने वाली आतंकवादी घटना हो, चाहे जहानाबाद में आतंकवादियों और नक्सलवादियों द्वारा की गई वारदात हो, वे सब इस सरकार की सोच का परिचायक थे कि बिलकुल कैज़ुअल तरीके से और सरसरी तौर पर या कर्मकांड के आधार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया।

आज 32 दिन हो गये हैं दिल्ली में बम विस्फोट हुए। हम सब जानते हैं कि दीवाली से दो दिन पहले दिल्ली में तीन जगहों पर बम विस्फोट किये गये। दिल्ली एक बार फिर से धधक उठी, धू-धू करके अनेक मार्केट जल रहे थे और

उनके साथ ही कई चिराग दीवाली की रात से पहले यहां बुझ गये। अनेक बच्चे अनाथ हो गये, कई महिलाएं विधवा हो गईं । 70 लोग मारे गये और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गये। यह एक ऐसा नृशंस हत्याकांड था कि उन शवों को देखने के लिए भी लोहे का दिल चाहिए था हमने उन शवों को देखा था। 32 दिन बीतने के बाद आज क्या स्थिति है, उस विषय में समाचार पत्रों में जो लिखा गया है, उसे देखने की आवश्यकता थी। अगर उन सबको देखा जाता तो शायद गृह मंत्री जी अधिक संवेदना के साथ, अधिक दृढ़ता के साथ अपनी कुछ बातें कह सकते थे। समाचार पत्रों ने लिखा कि 70 लोगों की मृत्यु हो गई, 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, 19 लोग आज भी अस्पतालों में हैं और चार शवों की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पायी है। अनेक शवों का अनेक परिवारों ने मिलकर संस्कार कर डाला । उन शवों की पहचान नहीं हो सकती थी और पहचान न होने के कारण उनके संबंधी और रिश्तेदारों ने मिलकर सामूहिक तौर पर उनका संस्कार किया था। एक समाचार में कहा है कि Even after 31 days the mother does not know where her son has gone. मां घायल अवस्था में हैं, इसलिए उसे आज भी पता नहीं है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। ""I have still not told my wife that our child is dead. My wife has finalised a name for her baby. She keeps asking about her and sooner or later I have to tell her that her baby is dead."

उपाध्यक्ष महोदय, हमने पीड़ित परिवारों के घरों में जाकर देखा, उनसे बातचीत की। रोंगटे खड़े कर देने वाली उन परिवारों की स्थिति है। एक परिवार में Parents and grand parents are dead now. माता-पिता उसी दिन मर गये। एक मात्र

संभालने वाला जो दादा था, वह उसी दिन से बीमार हो गया, जो उन बच्चों को पाल सकता था, उसकी भी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जो उस समय परिस्थितियां निर्मित हुईं, उनके विषय में सही प्रकार से इस बात को कहा गया "the serial explosions that ripped through Delhi leaving 70 dead and more than 100 injured were the biggest terrorists' strike in India outside Kashmir since the Bombay blasts of 1993; unlike the attack on Parliament in 2001 or even in Red Fort in 2000. The Delhi bombings were not directed at the symbols of the State but at the heart of the nation, their targets were not institutions of power but people, average Indians everywhere." हिंदुस्तान के दिल दिल्ली के ऊपर यह पहला आक्रमण नहीं था, इससे पहले भी ऐसी घटनाएँ हुई हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि आम तौर पर दीवाली से पहले, त्यौहारों से पहले उन आतंकवादियों के मन में एक खौफ पैदा किया जाता था, उन्हें रोकने की कोशिश की जाती थी और इसीलिए वर्षों तक ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई। परंतु इस बार दीवाली औऱ ईद के पहले कोई इस प्रकार का प्रबंध नहीं किया गया। यह कहना बिल्कुल गलत है कि किसी बाजार में पुलिस के पूरे प्रबंध थे, वहां कैमरे लगे थे। आतंकवादियों ने आकर कई दिन पहले देखा कि बाजारों में कोई पुलिस प्रबंध नहीं है । जब डार को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने बताया कि उसे लश्करे तैय्यबा ने भेजा, उसने आकर देखा कि कौन-कौन से बाजार बिल्कुल खाली रहते हैं, जहां पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है। इसलिए उन्होंने इन जगहों को छांटकर वहाँ आक्रमण किया। अब जिस डार को पकड़ा गया है, उसके बारे में गृह मंत्री जी ने उल्लेख किया कि उसे गिरफ्तार किया गया है। परंतु यह भी सब जानते हैं 29/10 को बम फैंकने वाले फरार हैं ।

बम डालने वाले पकड़े नहीं गये जिन्होंने दिल्ली में विस्फोट किए । जिन्होंने इतने लोगों की नृशंस हत्या की, उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई उन्हें धन देने वाला, षडय़ंत्र रचने वाला - डार, केवल वहीं पकड़ा गया । गिरफ्तारी के बाद जो बयान उसने न्यायालय में दिया है, वह अत्यधिक रहस्योद्घाटक है, हमारे लिए अत्यधिक चिंताजनक है। उसने बताया कि किस तरह से लश्करे तैय्यबा ने उसे जेहाद में लगाया। उनसे उसे कितने रूपये मिले । पाकिस्तान से उसे कितने रूपये मिले, कैसे पाकिस्तान में जेहादियों से उसकी बातचीत हुई। यह समाचार "Dar in court admits Pak hand in Delhi blasts" has appeared in the newspaper. उसने साफ तौर पर बताया कि पाकिस्तान ने किस प्रकार से इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि बम विस्फोटक में से कोई पकड़ा नहीं गया। मैं इससे अधिक महत्व की एक दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री शिवराज जी ने सदन में बयान देते हुए कहा था कि उन्हें, उनकी पुलिस को इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि दिल्ली में हमला होने के संबंध में पहले से कोई जानकारी नहीं थी या पहले कोई चेतावनी प्राप्त नहीं हुई थी । यह पूरी तरह से असत्य और मिथ्या बयान है। सारे समाचार पत्रों ने और पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है कि इन बम विस्फोटों की पहले से चेतावनी थी। केवल चेतावनी ही नहीं थी, बल्कि 13 अक्तूबर 2005 को समाचार पत्रों में छपा था कि Hyderabad and Cyberabad Police have stepped up security for American companies and US nationals following the alarm

out by United States' Embassy on likelihood of terrorist attacks against establishments and citizens in Hyderabad, New Delhi, Bombay and Calcutta. समाचार पत्रों में उस दिन यह छपा और सारे पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को माना और विस्फोट वाले दिन कहा कि हमें सूचना थी और हमने इसीलिए चांदनी चौक में एक बम पकड़ भी लिया था। मेरी राय में यह मामला संसदीय प्रिविलेज का भी बनता है कि सदन में गृह मंत्री जी यह कह दें कि कोई पूर्व चेतावनी नहीं थी। जबकि चेतावनी थी फिर यह तो सामान्य चेतावनी हर त्योहार से पहले रहती है। हर त्योहार से पहले इस बात की आशंका रहती है इसलिए इस दीवाली से पूर्व यह कहना कि चेतावनी नहीं थी, गृह मंत्रालय को मालूम नहीं था, अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया - यह ठीक नहीं है। अमेरिकन अधिकारियों ने अपनी एम्बैसी को लिखा और कहा कि दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर और कोलकाता में हमला हो सकता है। इसके बाद भी यह कहना कि हमें पता नहीं था, यह निष्क्रियता और आपराधिक लापरवाही नहीं तो और क्या है?

अध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय की विशेष शाखा को विस्फोट से पहले खुफिया जानकारी मुहैया कराई गई थी लेकिन वे उस पर कार्रवाई नहीं कर सके। संसद पर हमले के बाद यह दिल्ली में सबसे ज़बर्दस्त विस्फोट हुआ और वह भी एक प्रमुख त्योहार से पहले हुआ जिसको रोकने में सरकार नाकाम रही। आतंकवादियों से निपटने का एक तरीका यह है कि उन्हें महत्वपूर्ण मौकों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और त्योहारों से पहले आतंकित किया जाए। इस साल उसका पालन नहीं किया गया और उसका भयावह नतीजा हमारे सामने आया। इसके बाद जो

वक्तव्य गृह मंत्री जी ने दिए और मनमोहन सिंह जी ने भी जिसका उल्लेख किया कि आतंकवादियों की घिनौनी कोशिशों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। आतंकवाद हमें नहीं डरा सकता, आतंकवाद कामयाब नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, इन बयानों का क्या मतलब है? जिस देश में 80000 लोग आतंकवाद के हाथों मारे जा चुके हैं और लाखों-करोड़ों रुपये की संपत्ति नष्ट की जा चुकी हो, वहां यह बयान देने का क्या अर्थ है कि आतंकवादियों की घिनौनी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे? विश्व में सबसे अधिक आतंकवाद से ग्रस्त हिन्दुस्तान है। आप कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को कामयाब नहीं होने देंगे। दिल्ली में 70 आदमियों को मार डाला गया और 300 को घायल कर दिया गया, बम से उनके ऐसे चिथड़े उड़ा दिये गये कि उनकी शक्लें भी पहचानी नहीं जा रही थीं, वहां ये कह रहे हैं कि आतंकवाद कामयाब नहीं हो रहा है। वास्तव में तो आतंकवाद अपने उद्देश्य में कामयाब हो रहा है। प्रधान मंत्री का कहना है कि आतंकवाद हमें डरा नहीं सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम आतंकवाद को, आतंकवादियों को डरा सकते हैं या नहीं। सवाल यह नहीं है कि आतंकवाद से हम भयभीत होंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या आतंकवाद हमसे भयभीत होगा या नहीं, आतंकवाद हमसे डरेगा या नहीं, आतंकवाद को हम खत्म कर सकेंगे या नहीं। आतंकवाद हमें खत्म नहीं कर सकता यह हम जानते हैं। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहना बहुत घिसा-पिटा और पुराना तरीका है कि आतंकवादी आए और हमले में 70 आदमी मर गए, परंतु फिर भी लोगों ने कामकाज जारी रखा, हम डरे नहीं, हम उसी तरह से फिर कामकाज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 60000 लोग मारे गए और कहते हैं कि

आतंकवादी हमें भयभीत नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि हमने इतिहास से कोई सबक नहीं सीखा है। यही बात हम कहते थे कि महमूद गजनवी आया, हमला किया और वापस चला गया। हमने कहा कि हमारा क्या बिगाड़ गया, कुछ लोगों को मार गया। हम फिर भी जिंदा हैं और कामकाज में लगे हैं उसके बाद वह दोबारा आया और फिर बार-बार आया। क्या आतंकवाद से हम उससे भयभीत नहीं होते और हत्याओं के बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं। यह बहुत ही घिसा-पिटा, पुराना, विनाशक और बहुत ही कायराना .*प्रतिक्रिया है। यह कहना कि हम पाकिस्तान से डर नहीं रहे हैं। यह कैसी प्रतिक्रिया है? पाकिस्तान से डरने का सवाल नहीं है। क्या पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करते हुए हमसे डरता है? क्या हम इस पाकिस्तान से दो टूक बात कर सकते है या नहीं ? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, जब माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि दिल्ली के बम विस्फोटों के संबंध में पड़ोसी देश पर शक की निगाह जा रही है। उसकी ओर से ही आतंकवादी घटनाएँ हो रही है। क्या उस पड़ोसी का नाम लेने में तकलीफ होती है, उसका नाम लेने में कष्ट होता है, घूंघट क्यों डाल रखा है? हमारे यहां बड़े लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं? पाकिस्तान का नाम लेने से आपको घबराहट क्यों होती है। पाकिस्तान का नाम लेने में क्या तकलीफ होती है? हमारी सेना के अधिकारी कह रहे है। पाकिस्तानी जो पकड़े गए हैं, वे भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। जितने लोग अयोध्या में आक्रमण करने वाले थे, राम मंदिर पर हमला करने वाले पकड़े गए थे, वे सभी पाकिस्तानी थे। दिल्ली में कम से कम दो सौ पाकिस्तानी आतंकवाद के आरोप में पकड़े गए। इतना

आरडीएक्स बरामद हुआ, जिससे सारी दिल्ली को नष्ट किया जा सकता था, कहते हैं कि उसका नाम नहीं लेंगे । यदि आप नाम नहीं लेंगे, तो विश्व के देशों में आतंकवादी पाकिस्तान के बारे में स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे? किस प्रकार से इस बात को कहेंगे और ऐसा कहने का अधिकार हमें कैसे मिलेगा कि पाकिस्तान ये सभी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में करवा रहा है। हम ही नाम नहीं ले रहे हैं, तो पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, उसके बारे में हमारे सेनाधिकारी कह रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तान यह सब कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा सारे देश में आतंकवाद फैलाने के प्रयास पहले की तरह ही कायम हैं।

दिल्ली के विस्फोटों के संदर्भ में इस घिसे-पीटे तर्क का कोई मूल्य नहीं है कि आतंकवादी हताश हो कर यह सब कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिल्ली की घटना आतंकवादियों के दुस्साहस का परिचायक है। यह उनकी निराशा का परिचायक नहीं है यह उनका दुस्साहस है, एक साजिश है, उसका यह नतीजा है।

सदन में कश्मीर पर बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि जिस दिन हमारे मित्र श्री आजाद साहब वहां पर मुख्यमंत्री बन कर गए, उनकी ताजपोशी हो रही थी, उस समय आतंकियों ने आजाद साहब को तोहफा दिया और 12 लोग मारे गए। अखबारों में छपाः "Jaish

*Expuinged as ordered by the Chair

car bomb kills seven a day before Azad took charge in Srinagar". "Hours before Ghulam Nabi Azad was sworn in as new Chief Minister of Jammu & Kashmir today, a powerful explosion of Srinagar outskirts killed seven people including four civilians. Jaish-e-Mohammed later called a local news agency and claimed responsibility for the blast." "Terror gift for Azad on day one. Suicide Bomb. Five killed." "सीआरपीएफ शिविरों पर हमला", "कश्मीर में दो आतंकवादियों सहित पांच मारे गए। " तीन दिन तक लगातार विस्फोट होते रहे। कुल-मिला कर 40-50 लोग मारे गए । पाकिस्तान के साथ कैसी-कैसी बातें हुईं, ये सब समाचार पत्रों में आया है। कश्मीर में ऐसी भीषण स्थिति है और मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं - गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि जब कभी भी कश्मीर में नया शासन आता है, तो ऐसी घटनाएँ होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कोई और क्या वीभत्स वक्तव्य हो सकता है कि जब सरकार बदलती है, जब नया शासन आता है, तो वहां ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती हैं। जब श्री गुलामनबी आजाद वहां नए मुख्य मंत्री के पद की शपथ ले रहे थे तब वहां आतंकवादी घटनाएं घटीं। "They have taken their own time." इससे पहले जब श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने शपथ ली, तब भी वहां आतंकवादी घटनाएं हुईं। जब-जब नया शासन आया, तब-तब आतंकवादी घटनाएं हुईं, क्या ऐसा उत्तर लोक सभा में दिया जाना चाहिए ?

यदि आपको पता था कि जब भी नया शासन आता है, तब आतंकवादी घटनाएं होती हैं और चूंकि मुफ्ती मोहम्मद साहब हट रहे थे और श्री गुलाम नबी आजाद साहब आ रहे थे, इसलिए आतंकवादी घटनाएं हुईं, तो आपने उन्हें रोकने

के लिए क्या किया ? पूर्वानुमान होते हुए आपने आतंकवादी घटनाओं को क्यों नहीं रोका ?

उपाध्यक्ष महोदय, जब ये घटनाएं वहां हो रह थीं, उससे पूर्व वहां बहुत बड़ा भूकम्प भी आया जिसके कारण वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई। हमारे कश्मीर में भी तबाही हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी तबाही हुई। स्वाभाविक तौर पर उनकी सहायता की जानी चाहिए थी और हम कर भी रहे थे। हमने पाकिस्तान को 25 मिलियन डॉलर दिए। हमने लगभग 100 करोड़ रुपए पाकिस्तान भेजे और हमने पांच जगह सीमा खोली और ऐसा कर हमने उनका विश्वास जीतने का प्रयास किया । यह मानवता के आधार पर किया जाना चाहिए था और हमने यह किया।

लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है ? हमारी सेना के उच्चाधिकारी कह रहे हैं कि भूकम्प आने के बाद और सीमाएं खोलने पर लगभग 400-500 आतंकवादी श्रीनगर में घुस आए हैं। उन्हें रोकना सम्भव नहीं हो सका। अब वे वहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या मानवता के आधार पर किए गए काम का नाजायज लाभ पाकिस्तान को उठाना चाहिए, क्या ऐसा करना उनके लिए उचित है ? इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां वे वहां से हिन्दुस्तान आकर क्यों रहे हैं, क्यों दिल्ली में बम विस्फोट कर रहे हैं ? इस प्रश्न को कौन उठाएगा और किसके साथ उठाया जाएगा ? क्या हमारी प्राथमिकताओं में यह है कि हम आतंकवाद को रोकें

या प्राथमिकता यह है कि हम बॉर्डर को खोल दें, एल.ओ.सी. को खोल दें और उसका अनुचित लाभ वे लोग उठाते रहें ?

महोदय, हमने पाकिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उस सहायता का क्या हो रहा है, क्या किसी ने देखने की कोशिश की ? जो पैसा वहां जा रहा है, कहा जा रहा है कि उससे भूकम्प पीड़ितों को मकान बनाकर नहीं दिए जा रहे। जो धन यहां से जा रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है, इसको कोई देखने वाला नही है। पाकिस्तान के सदस्यों ने अपनी पार्लियामेंट में स्वयं कहा कि बजाय भूकम्प पीड़ितों की सहायता करने के पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। विदेशों से उसे 5 बिलियन डॉलर की मदद मिली है, उससे वह हथियार खरीद रहा है। भारत में आतंकवादियों को भेजकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर हमारी सहायता का नाजायज फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भूचाल के कारण जो विनाश हुआ था, उसे वह नहीं बना रहा है, बल्कि जो आतंकवादियों के अड्डे थे और आतंकवाद का जो जो इफ्रास्ट्रक्चर तहस-नहस हो गया था, हमारी सहायता राशि से वह उसे बनाने में लगा हुआ है। क्या हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि जो रुपए हम सहायता के रूप में दे रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं ?

महोदय, भारत ने कहा था कि हमारे लोग भूकम्प पीड़ित क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों को सहायता पहुंचाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया कि सहायता हमें दे दो, हम पहुंचाएंगे, भारतीयों को वहां नहीं जाने दिया गया। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब हिन्दुस्तान के गुजरात राज्य में भूकम्प आया था, तो हमने सबसे कहा कि वहां जाओ, देखो और जो सहायता कर सकते हो, करो।

हमने किसी देश को वहां आने से नहीं रोका, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमें रुपए दे दे, हमें सहायता दे दो, हम पहुंचाएंगे, हिन्दुस्तानियों को अपने क्षेत्र में नहीं जाने देंगे।

प्रेम लता मैं बताना चाहता हूं कि जो सहायता पाकिस्तान को भूकम्प पीड़ितों को दे रहे हैं, वह जेहादियों के हाथ में जा रही है। वे अपना इफ्रास्ट्रक्चर फिर से बिल्ट कर रहे हैं। सहायता का लाभ जेहादी और आकंतवादी उठा रहे हैं। क्या हमने अपने 100 करोड़ रुपए जेहादियों को उनका इफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए, क्या हमने पाकिस्तान को वह सहायता हथियार खरीदने के लिए दी ? इस बारे में हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात क्यों नहीं करती है ? हमारी गवर्नमेंट बजाय इस बारे में बात करने के, उल्टे कहती है कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत जारी रहेगी। कॉन्फीडेंस बिल्डिंग मैजर्स के नाम पर हमारी सीमाएं खोली जाएंगी, हमारी एल.ओ.सी. खोली जाएगी, जो हमारी बातचीत चल रही है, वह चलती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक इंटैलीजेंस ऑफीसर ने जो स्टेटमेंट दिया था, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं।

You cannot hold hand with General Musharraf in New York and refuse to castigate Pakistan for its continued support to cross border terrorism except to fight terror in India. आप मुशर्रफ जी से बातचीत करें और उसके बाद वहां पाकिस्तान का नाम लेने से भी इन्कार कर दें कि पाकिस्तान ये सारी आतंकवादी

घटनाएं कर रहा है। फिर यह उम्मीद करें कि हमारे सैनिक, सैन्यबल, यहां नई दिल्ली में और वहां जाकर टेरेरिज़्म को खत्म करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। समझ में नहीं आता कि यह गवर्नमेंट कौन सा मेसेज़ उन्हें देना चाहती है या सरकार क्या संदेश देना चाहती है। टेरेरिज़्म खत्म करने का संदेश देना चाहती है या पाकिस्तान से दोस्ती का संदेश देना चाहती है। पाकिस्तान टेरेरिज़्म करता जाए और फिर भी हमारा दोस्ती का हाथ बढ़ता ही रहेगा। अगर यह स्थिति है तो कौन वहां जाकर उनसे लड़ सकता है या झगड़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह स्टेटमेंट पढ़ कर सुनाता हूं। मुज़ामिल जलील का, वहां के रिपोर्टर का स्टेटमेंट है - "Terror sneaks in through quake cracks -- When the devastating earthquake set off a fresh wave of peace and cooperation along the Line of Control, the J-K Police says, foreign militants infiltrated into the Valley in large numbers. Around 125 of them are suspected to have entered Srinagar city which has witnessed a sudden spurt of *fidayeen* and car bomb attacks." ये श्रीनगर से हमारी सेना, पुलिस का बयान है। वहां पर मुज़ामिल जलील ने इस बयान को दिया। आगे फिर कहा है, हमारे वहां जो जनरल हैं, Col. V. K. Batra said that the Army foiled three to four infiltration bids since the quake. "We killed 21 militants trying to infiltrate. However, some groups might have managed to sneak in taking advantage of the post-earthquake situation," he said. He too put the number of militants operating inside Srinagar city at around 100 as per the figures of various intelligence agencies.

उपाध्यक्ष महोदय, क्या दुनिया में कोई देश ऐसा हो सकता है कि भूकम्प आए और उसका फायदा उठा कर, भारत जो उसकी सहायता कर रहा है, उसी के

खिलाफ वे अपना जेहाद शुरु कर दें। यह स्थिति वहां की है। इसलिए मैंने आपसे उल्लेख किया कि यह जो काश्मीर के अंदर स्थिति है, और उनके दोनों बयान, जो कि हमारे सामने कहे गए, उन बयानों के बारे में यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां अमेरिका के विषय में भी, हालांकि 9/11, जो अमेरिका में हुआ था, उसकी जांच के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया था और वह जो कमीशन था, उसका यह कहना है- "Pakistan continues to be a sanctuary and training ground for terrorists, a report on the status of recommendations made by the 9/11 Commission on terror attacks in the US has said, asking Washington to put pressure on the Government of Gen. Pervez Musharraf to stop the menace in his country and also in Kashmir. "Pakistan remains a sanctuary and training ground for terrorists," said a report by Mr. Lee Hamiliton, the Vice-Chairman of the 9/11 public disclosure project, which examined action taken by the US administration on the recommendations of the Commission that probed."

उपाध्यक्ष महोदय, उसने आगे कहा है - "Taliban forces still pass freely across Pakistan-Afghanistan border and operate in Pakistani tribal areas. Terrorists from Pakistan carry out operations in Kashmir. Finally, the results."

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पाकिस्तान कश्मीर के आंतकवाद को बढ़ावा दे रहा है परन्तु अमेरिका का रवैया आतंकवाद के प्रति ठीक नहीं है। वे एक तरफ तो कहते हैं कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ विश्वभर में लड़ेगा और दूसरी तरफ सबसे अधिक आतंकवादी देश पाकिस्तान की वह खुली मदद भी कर रहा है, उसे धन देता है, हथियार देता है और पाकिस्तान

से जो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसे रोकने के लिए, पाकिस्तान पर दबाव नहीं देता।

वैसे तो अमेरिका ने ही तालिबान को पैदा किया था, अमेरिका ने ही दुनिया में बहुत से आतंकवादी संगठनों को पैदा किया, परन्तु आज पाकिस्तान भी.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not make running commentary, please.

मल्होत्रा जी, आप कण्टीन्यू करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, उसे आगरा से हमने खाली हाथ वापस भेज दिया था। आपकी तरह से तश्तरी में रखकर उनको कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा नहीं दिया, हमने उससे जमीन खाली करा ली थी।.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Manvendra Singh, why are you interfering? Please sit down.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : हमने एक इंच जमीन नहीं दी, आपने हिन्दुस्तान की एक लाख किलोमीटर जमीन पाकिस्तान और चीन को दे दी।.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको किसी ने बोलने का टाइम दिया है? Mr.Manvendra Singh, please take your seat.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं आप से जिक्र कर रहा था कि जो दबाव अमेरिका को देना चाहिए था और कम्युनिस्ट भाई इस बात का जिक्र कर रहे थे और अमेरिका की और बातों के बारे में कह रहे थे, वोल्कर रिपोर्ट का आज जिक्र नहीं है। उसमें भी समर्थन किया क्योंकि अमेरिका की बात है। यह सरकार जितनी अमेरिकापरस्त है, इतनी आज से पहले कभी कोई सरकार नहीं रही। अमेरिका के आगे पूरे घुटने टेके हुए हैं। अमेरिका से मिलकर यहां पर सैन्य

अभियान पूरा होता है। अमेरिका के साथ मिलकर यहां पर हम ईरान के खिलाफ सैंक्शंस करते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर हम परमाणु बम सन्धि पर हस्ताक्षर करते हैं। परन्तु अमेरिका से भी हमें इस बात को कहना चाहिए.(व्यवधान)

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): They are more Americans than you. (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अमेरिका से भारत को बात करनी चाहिए थी। परन्तु अगर हम खुद ही पाकिस्तान की निन्दा नहीं करेंगे तो अमेरिका से क्या कहेंगे। परन्तु अमेरिका के साथ जब कभी बातचीत हो तो पहला सवाल यह होना चाहिए कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दिल्ली के बम विस्फोटों पर विचार किया गया। "Delhi Bomb blast question was discussed in the British Parliament. प्रस्ताव में कहा गया 'Attack on one democracy is an attack on all democracies.' उन्होंने कहा कि आतंकवादी किसी भी रूप में कहीं भी हो, उसके खिलाफ सब को मिलकर लड़ना चाहिए और हम हिन्दुस्तान की मदद करने को तैयार हैं। सार्क सम्मेलन हो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हो, यू.एन.ओ. हो, फ्रांस हो, चीन हो, जिससे भी हमारी बातचीत होती है, सभी कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया भर को एक सामुहिक प्रयास करना चाहिए परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हिन्दुस्तान का आतंकवाद अन्य देश समाप्त करेंगे? सवाल यह नहीं है कि सारी दुनिया आतंकवाद से दुखी है, मदद करना चाहती है, लेकिन क्या हम खुद आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं? क्या हमारी नीतियां आतंकवाद खत्म करने के लिए हैं या हमारी नीतियां आतंकवाद को प्रोत्साहन देने

के लिए हैं? मेरा आरोप है कि हम आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम आतंकवादियों को खुला छोड़ रहे हैं और उनका आसान निशाना बन रहे हैं, जब चाहे, जहां चाहे आकर वे आक्रमण करें, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा देश है तो मुझे बताइये, जिसने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाये। कानून बनाये, भयंकर कानून बनाये और अत्यंत सख्त कानून बनाये हैं और हमने क्या किया, हमारे यहां एकमात्र पोटा का कानून था। हमारा ऐसा बदकिस्मत देश है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद है, सबसे ज्यादा लोगों को जिसमें आतंकवादियों ने मारा है.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Prof. Malhotra. कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है।

(Interruptions) .*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Manvendra Singh, please sit down.

. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will not go on record.

(Interruptions) .*

* Not Recorded.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आप जिस तरह से आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको बताएंगी कि आपने क्या किया था। आप जब भाषण देंगे, वह आप तब बताइये। आपकी पार्टी के बहुत से स्पीकर्स बोलने वाले हैं, इसलिए सिब्बल साहब को बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। .(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आपको तो नहीं बोलना चाहिए।

.(<u>व्यवधान</u>)

उपाध्यक्ष महोदय : मानवेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये।

<u>15.00 hrs</u>

. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Nothing is to be recorded.

(Interruptions) .*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Not even a single word of other hon. Members is to be recorded.

(Interruptions) .*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing is to be recorded.

(Interruptions) .*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटेन का कानून हमारे कानून से दस गुना ज्यादा सख्त है। अब वे एक और कानून बनाने जा रहे हैं। यह ठीक है कि भारत कोई पुलिस स्टेट नहीं है, हमारे यहां कोई एक तंत्र या राजतत्र नहीं है, लेकिन हमें यह भी तो समझना चाहिए कि हम आतंकवाद से ग्रसित देश हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आंतकवाद के विरूद्ध एक ही कानून था, जिसको हटा दिया गया। आप सभी को मालूम है कि अब पोटा समाप्त कर दिया गया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि किसी अपराधी को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। आतंकवादी कितने ही लोगों को मार दें, लेकिन अब उनको फांसी नहीं दी जाएगी। अब आंतकवादियों के विरूद्ध पोटा तो रहा नहीं बल्कि उनको महिमा-मंडित किया जा रहा है। गिलानी को नायक बनाकर पेश किया गया। इशरत को

जाकर एक लाख रूपये का ईनाम दिया गया था। जबकि वह आतंकवादी गुट में शामिल थी।

* Not Recorded.

मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहना चाहता। तीसरा है, नक्सलवाद। जहांनाबाद के अंदर नक्सलवादियों द्वारा हमला किया गया। इसमें आंकड़े दिए गए हैं कि पिछले वर्षों में कितने आदमी मारे गए। नक्सलवादियों से कितने लोग प्रभावित हुए। नक्सलवाद की अब तक 1138 घटनाएं हुई हैं, जिनमें सात-आठ सौ व्यक्ति मारे जा चुके हैं। 2003 तक देश के 25 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे, अब उनकी संख्या बढ़कर सवा सौ हो गई है। जब से यह सरकार आयी है, 6 महीने के अंदर-अंदर दो सौ जिले नक्सलवाद से ग्रस्त हो चुके हैं। नक्सलवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप अपने चुनाव के लिए उनसे हाथ मिलाते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनकी मदद लेते हैं। उनको अपने साथ लेकर चुनाव में चन्द सीट जीतने के लिए देश को बर्बाद करते हैं। यह नक्सलवादी कहां से आ रहे हैं? यह नेपाल से आ रहे हैं । नेपाल के 75 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हैं। चीन उनको मदद नहीं कर रहा है, बल्कि उसने तो नेपाल के महाराजा को हथियार भेजे हैं। नक्सलवादियों को हिन्दुस्तान से हथियार भेजे जा रहे हैं। सीपीएम, सीपीआई, बंगाल और असम सभी उससे ग्रस्त हैं। नक्सलवादी जिस प्रकार से पूरे देश में फैलता चला जा रहा है, उसकी जिम्मेदार यह यूपीए सरकार है।

मैं एक ओर बात का उल्लेख करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आईएमडीटी एक्ट को खत्म करने पर टिप्पणी की थी। यदि सरकार में

नैतिकता नाम की चीज है तो उसे सुनकर सचमुच उन्हें सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंग्लादेश से घुसपैठ, देश के ऊपर एक तरह से आक्रमण हो रहा है और हम उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम उस पर ध्यान न देकर देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेशियों को यहां से न निकालकर और आईएमडीटी एक्ट खत्म न करके इस देश की सुरक्षा को राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतृत्व खतरे में डाल रहा है। उधर जस्टिस लाहौटी ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए और इस समय यह राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है।

पोलीटिकल विल नहीं है, इसलिए आतंकवाद के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय आपके खिलाफ आते हैं प्रश्न यह नहीं है कि तब क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किसने क्या किया था, परन्तु नीति का सवाल है। आप पोटा खत्म करेंगे, बंगलादेश से लोग आते जाएंगे, आप आतंकवादियों और नक्सलाइट्स से मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे और देश की.(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : कहां मिलकर चुनाव लड़ेंगे?.(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ा, आसाम में चुनाव लड़ा, बिहार में उनसे मदद ली।.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय,, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि चाहे नक्सलवादियों का मामला हो, जिसके बारे में यहां उल्लेख हुआ, चाहे कश्मीर के बम विस्फोट का

मामला हो, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमें दुनियाभर में पाकिस्तान के मनसूबों को साफ करना चाहिए। यह नहीं कि पाकिस्तान से हमारी बातचीत हो रही है, कहीं यह न चला जाए कि बातचीत में थोड़ी दिक्कत हो गई और हमारे माइनॉरिटी वोट न टूट जाएं। अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाते। आप आतंकवाद के खिलाफ भी इसलिए कदम नहीं उठाते कि आपके मुस्लिम वोटों पर फर्क पड़ जाएगा। आप उनके वोट लेने की खातिर देश को संकट में डाल रहे हैं।.(व्यवधान) हम आप पर आरोप लगाना चाहते हैं, हमारा प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह पर आरोप है, we charge him of betraying the confidence of our nation imposed on him for winning a few seats.

We impeach this Government of betraying the nation for vote bank politics. अब तो वोट बैंक पोलीटिक्स नहीं बल्कि नोट बैंक पोलीटिक्स हो गई है जो वोल्कर रिपोर्ट से साबित हुई।.(व्यवधान)

मैं कहना चाहता हूं कि

> "The waffling on Punjab and Manipur, the dismantling of the Hurriyat initiative through benign neglect and, finally the over-politicised withdrawal of POTA add up to formidable evidence of a combination of spinelessness and intellectual bankruptcy on issues of internal security. Surely, that is not what Shri Manmohan Singh wishes to end up with so soon in his tenure."

18 महीने के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को इस सरकार ने तार-तार कर दिया। देश में किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा न हो कि आप अल्पसंख्यक वोट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान को, नक्सलवादियों

को, मदरसों को, बंगलादेश की घुसपैठ को उसी प्रकार बढ़ावा देते रहे और देश की सुरक्षा को तार-तार कर दें, ऐसा न हो कि मीर जाफर और जयचन्द का इतिहास फिर से लिखा जाए, उनके नाम के साथ आपको याद किया जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा खतरे में मत डालिए।

SHRI AJOY CHAKRABORTY (BASIRHAT): Thank you, Hon.Deputy Speaker, Sir. The subject of discussion arises out of tabling of the four statements made by the hon. Home Minister before this august House. Two statements relate to the naxal attacks and two statements relate to the incidents of fundamentalist militant group's attack. The naxal attack took place on 11th November 2005 at Giridih Home Guard Training Camp and police camp at Jharkhand.

Another attack was effected by the Naxalites on the 15th of November, 2005 at Jehanabad jail and also at other places in Jehanabad in the State of Bihar. Then, another incident of terrorist attack effected by fundamentalist militant groups, took place in the capital of country on the 29th of October this year. A series of terrorist attacks took place on the 14th, 15th and 16th of November this year in the State of Jammu and Kashmir during the time when our former Parliamentary Affairs Minister and our distinguished colleague, Shri Ghulam Nabi Azad took oath as the new Chief Minister of that particular State.

Sir, I heard, with rapt attention, the speech of Prof. Vijay Kumar Malhortra. He is a very senior colleague of ours. The impression I got from what he said was that he wants a total war to be declared against Pakistan as well as Bangladesh in order to curb this menace of militancy in our country. I would not like to dwell on that point.

Sir, two kinds of attacks are being talked about - one is the attack by the Naxalites and another is the attack by the fundamentalist militant groups. I would, first, like to refer to the Naxalite attack at Giridh in Jharkhand and at Jehanabad in Bihar. I do not agree with what has been said by Prof. Malhotra in regard to

Naxalite activities. He, in his speech, has accused the Government at the Centre saying that for the purpose of winning the last elections in the State, the Central Government had colluded with the Naxalite groups. The Central Government was hobnobbing with the Naxalite groups only for the purpose of winning the electoral battle in the State. That is not the fact.

Sir, we must have to find out the root cause as to why the Naxalite activities are taking place in our country. The Naxalite movements in different States like Jharkhand, Bihar, Maharashtra, Andhra Pradesh, Maharashtra have started because of some reasons. There are reasons behind it. What are those reasons? The reasons primarily are hunger, starvation and deprivation. It is since 58 years that we have got Independence. At the time of our Independence our leaders promised to the nation that we shall look after the welfare of the poor; we shall look after the welfare of the down-trodden; we shall look after those people who are living in the remote areas of this country, completely detached from the urban areas. But what has happened? Only some sections of people have grown richer by the day and a vast majority of people in this country have become poorer with passage of time.

Sir, who are these Naxalites? They are the people who have been deprived for all these years. They did not get land. Land reforms in the true sense has taken place only in three States, namely, West Bengal, Kerala and Tripura. Though a large number of States in this country have enacted legislation in regard to land reforms but the provisions of the Act has not been implemented in the States of Bihar, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra and such other States. There are in existence the *Kulaks* and the *Zamindars* in different States of our country. The lands are mostly occupied by these classes of *Kulaks* and *Zaminders.* The people belonging to the poorer sections of the society are mostly tribals or aboriginals and most of them belong either to the Scheduled Caste or to the Scheduled Tribes or to the *dalit* community. They are yet to be strengthened by the effect of the land reforms in this country.

Thousands and thousands of acres of land are wasted. Not a single *patta* is given to the tiller of the soil. They have got no land. They have become poorer and poorer day by day. We must go and look into the root causes of this problem. I think our colleagues will agree with me. Even Prof. Malhotra and his Party will agree with me that no AK-47 or the arms and ammunition or forces like the BSF can deal with the naxalites. They cannot combat the problem. Gun is not the solution to the naxal problem. The solution is that the poor and downtrodden people should be allotted land. They should be given their land back to them and should be given the right of the land which is their ancestral property. Due to poverty, they have sold it out to the landlords or some tillers or *kulaks*. Now the lands are in the hands of the landlords. Even after 57 years of our Independence, no land is distributed to the poor people excepting the States like West Bengal, Kerala and Tripura. No other State has done it. This is the fact. Nobody can deny it.

Who have created the naxal problem? The rulers of the country have created the naxal problem in our country. You go and see the position in big cities like Kolkata, Mumbai and Delhi. There are big five star hotels and behind them are the slums. The MPs and Ministers are enjoying their stay in the five star hotels like The Sheraton in Mumbai and Regency in Kolkata. There are big hotels in Delhi also. Behind such hotels are big slums. Poor people are living there. Why?

We are not supporting the political line of the naxalites. The CPI, the CPI(M) and other Left Parties have ideological differences with the naxalites. We do not support the political line of the naxals. But the question is more number of poor people are joining the naxal movement. They believe that this is the path and line they have to follow. They think that this is the line to follow against the people who are exploiting them. They are fighting against their exploiters. I urge upon the Government and the Opposition Parties to please implement the land reforms. They are capturing some State Administrations. I am urging you to eliminate poverty by implementing the land reforms. This is the only way to deal

with the naxals. The Chief Minister of West Bengal has declared it and the West Bengal Government has decided to start development works more vigorously in the villages and tribal areas. Our Chief Minister has requested the MPs of West Bengal to utilise the MPLAD funds for the development of the tribal areas. They are undeveloped. No development work has been done there since Independence. It is the duty of the State Government and the Central Government to look after proper implementation of the land reforms, proper development of the downtrodden people of the tribal areas and those who are living in the remote areas of the country. It is our duty to bring those people to the mainstream of the country so that they feel that they are living in the mainstream and are not subject to any sort of deprivation and negligence.

Coming to the aspect of fundamental militant group, my distinguished friend, Prof Malhotra said one point. I may be wrong. If I am wrong, I will be happy. He said that an immediate war should be declared against Pakistan to demolish Pakistan. He narrated some portions. But I say to Prof. Malhotra that humanity is above all these things. Indirectly he has been opposing opening the LOC to render financial assistance to the quake affected areas there.

He is opposing, in another way, to provide relief materials to the earthquake-victims of Pakistan. People of Pakistan are not our enemies. People of both Pakistan and India are friends. The common people of Pakistan want friendship with the people of India. We are Indians. We want friendship with the people of Pakistan. They are not our enemies. No doubt, their rulers create problems in our country. He was targeting Pakistan rulers and its President. I also agree with him. But the question is, who are the people who are pulling the strings from behind the scene. He said, that "I am happy, that the present Government is more pro-American than the NDA Government." I do not know which is more pro-American, whether it is the UPA Government or the NDA Government. I am not going into that matter. But the question is who are the creators of terrorism.*

* Expunged as ordered by the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER: These names will not go on record.

(Interruptions) .*

SHRI AJOY CHAKRABORTY : **The terrorism created by the fundamental militant groups is not just affecting India. The day before yesterday there was a serious bomb blast in Chittagong and Gazipur areas of Bangladesh. It had happened in Jordan. It had happened in different countries of the world. It is not the problem of India alone. No doubt, it is the greatest problem of our country. . (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : जो नाम माननीय सदस्य ले रहे हैं, उनको डिलीट कर दीजिए।

SHRI AJOY CHAKRABORTY : This is happening and this has happened in different countries of the world. This had happened in Sri Lanka, in Pakistan, in Bangladesh, day before yesterday, in Jordan, in Egypt, in U.K. and in U.S.A. Who has created terrorism? America has created all these problems.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This will be expunged.

(Interruptions) .*

SHRI AJOY CHAKRABORTY : They demolished Afghanistan. America destroyed Iraq. Is it for President Bush to decide as to who will be the President of Iraq?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not mention the names of our friendly countries in this way. They are our friendly countries. Do not take their names in this way.

(Interruptions).*

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, respectfully, I would like to say that American people are our friends.

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाम ले रहे हैं।

SHRI AJOY CHAKRABORTY : **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will not allow this. I will expunge them.

* Not Recorded.
* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, when America attacked Iraq, a discussion took place in this august House. They indiscriminately attacked Iraq.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can speak without mentioning names.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : They destroyed schools, colleges and hospitals in Iraq. They are the main terror**.** Our former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee went to New York and met President Bush and the present hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh also met President Bush. He assured them that they will see to it that Pakistan stops cross border terrorism. The American President came here. He met our leaders. He went to Pakistan also. He met Pakistan's President and other leaders. What happened thereafter? Had he sincerely and seriously tried to stop cross border terrorism, he must have warned President Musharaf not to indulge in cross border terrorism in our country, particularly in Kashmir. . (*Interruptions*)

Who is sponsoring Jaish-e-Mohamad, Lashkar-e-Toiba and Hizbul Mujahideen? No doubt, Pakistan is sponsoring them. Had America been sincere, eager or serious to stop cross border terrorism and destabilising our country, they could have stopped it. They could have warned President of Pakistan not to indulge in any activity that destabilises India.

These things are going on.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please conclude your speech now. I have a long list of speakers with me.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I am sorry to say, I was the prime mover. (*Interruptions*) It is a request.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party time is only 4 minutes.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, I should be given some more time. Actually, I have given the notice. You please see the List. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party time is only 4 minutes.

SHRI AJOY CHAKRABORTY : I shall conclude within 3 minutes. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Your party time was only 4 minutes but I have given you more than 15 minutes.

. (*Interruptions*)

SHRI AJOY CHAKRABORTY : Sir, I shall always carry out your orders. I shall conclude within 3 minutes.

Regarding the militant and fundamentalist groups, I say our Government should tread cautiously. I had a supplementary question day before yesterday also. Everybody knows what happened in Delhi. More than 60-70 lives had been lost. In one case, the children have lost their parents. Now, they have lost the grandparents after the assassination of their parents. The children are living under the blue sky. Even their father had taken a loan from a bank for construction of his house. Now, after the assassination of their parents and the death of their grandparents, the bank issued notice to the children to repay the loan taken for that house. Who will repay the loan of the bank?

Sir, I do not know whether the Government has declared ex-gratia relief to the victim families of those who were assassinated or were seriously injured. I do not know whether all the people have got the relief. After the intervention of hon. Speaker, I asked the Home Minister about this but there was no reply from him. During the course of the inquiry if it is revealed that there was a failure of the Intelligence Bureau or a failure of some police personnel or it was due to the negligent act of some police personnel, due to which that unfortunate happening took place in the heart of Delhi of our country, I urge the Government of India to modernize our police forces not only in Delhi but in other States also.

The Jharkhand Government as well as other States are urging the Government of India to render all possible financial assistance so that they can modernize their own police forces and armed forces. As regards Delhi police force, they are equipped with very sophisticated arms and ammunition. But the

position of other State Governments is that they are not getting or obtaining any financial assistance for upgrading and modernizing the police forces. I would urge before the Government of India to look into the matter seriously, tighten our security forces, upgrade and modernize all the police forces and boost the morale of the police forces so that they can combat with the militant and terrorist groups.

What happened in Kashmir? This is a new series of incidents which took place on the 14, 15 and 16 November of this year. This is a continuous process. So, we must earn the confidence of the people of the Jammu and Kashmir so that they can consider themselves the people of India. They can consider that they are the citizens of the independent country. If we do not boost the morale and earn the confidence of the people of Jammu & Kashmir, we cannot combat with these militant groups.

I would also like to draw the attention of the Home Ministry, because the Defence Minister is not here, that our Defence Forces, para-military forces, police forces should behave with the people of Jammu & Kashmir in a more friendly way. The people of Jammu and Kashmir should treat our forces as friend. The attitude of Force should be friendly to the people of Jammu and Kashmir. We should start a process to earn the confidence and faith of the people of Jammu and Kashmir. They are the citizens of independent India and they should not join the militant groups.

So, I hope the Government of India will look into the matter seriously and deal with the matter. I hope it is not a matter of any one political party or only the ruling party. It is a matter of the whole House. Cutting across party lines, we

should come together to fight against the militant groups and save our country from the hands of the militant groups sponsored by the foreign countries.

With these words, I conclude.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to intervene in the Discussion under Rule 193 raised by my good friend Prof. Malhotra.

Sir, I was very much saddened but not surprised by the tenor of the debate and the tenor of the comments made by my good friend. He started off by saying, by criticising the Prime Minister of India when he said that "we will not allow terrorism to succeed in India." He took exception to that statement and it is thereby implied that terrorism was successful in India.. (*Interruptions*) When the Prime Minister of India says "we will not allow terrorism to succeed" I hope he is speaking on behalf of the nation and that no political party in this country, no section of any community in this country will allow terrorism to succeed. When a leader of a major political party sitting in the Opposition says that terrorism is successful in India, I wonder what message he is sending to the terrorists in Pakistan. I think that leaders in the Opposition, merely because they are in the Opposition, should be concerned with national interest before they make statements like. They should not give a message to the terrorists that we are a nation divided. . (*Interruptions*) That message should never be given.. (*Interruptions*)

I remember that when terrorists attacked Parliament, when terrorists attacked the Akshardam Temple, when terrorists attacked our pilgrims on the Amarnath Yatra, when terrorists attacked people in Kashmir, when we were in the Opposition, we stood with the Government. So, I take exception to a party and to a leader of a party which calls itself nationalist, which is sending a message as if this is a nation divided.. (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): Shall I show you all the speeches made by your Members? . (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: We never interrupted you.. (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : You cannot say that you supported us. Shall I show you the speeches made by your party Members at that time? . (*Interruptions*) Shall I bring the speeches of your party Members who were in the Opposition at that time and show you?. (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: I am not yielding. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions are not to be recorded.

*(Interruptions)** .

SHRI KHARABELA SWAIN: You do not yield to me. Do not tell here that you supported us and you never opposed us. Do not say like this.

SHRI KAPIL SIBAL: If you are engulfed by darkness, try and light the lamp. It will give you some light instead of interrupting me.. (*Interruptions*)

Then, my learned friend said we never named Pakistan. What is happening today? There is an investigation going on. The investigation has not yet been completed. The case has not come to trial. No charge-sheet has been filed. Are we to believe that a responsible Government in this country will start naming nations, in particular investigations, before the charge-sheet is filed? That used to happen when they were in power.

When charge-sheets were filed, they used to say their leaders are not at fault even when they were charge-sheeted. It happened in the Ayodhya case. You used to say, "Advaniji is not at fault. He is innocent when a charge-sheet had been filed against him." These are acts of an irresponsible Government and irresponsible leaders. I want to assure this House that we do not want to follow your footsteps of irresponsibility. We are a responsible nation and a responsible Government, and we will name the country and the government only when we decide to file the charge-sheet and have proof against that country and that

Government. I am proud of the fact that my Prime Minister has taken this position. I am absolutely amazed. I remember when they were in power and

* Not Recorded.

terrorist attacks were taking place and the '*Lauh Purush*' was the Home Minister of India. I remember the famous statement which I can never efface from my mind. He said that after I have become the Minister, I will follow the policy of hot pursuit against Pakistan. All of us remember that. Now, that policy of hot pursuit was never followed. Then, he said, 'No', I have a proactive policy against Pakistan. Then, that proactive policy was also not followed. Then, it became a reactive policy. And ultimately it is an inactive policy. So, this was a journey from 'hot pursuit' to 'inactivity'. That is your track record on Pakistan and on terrorism.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not disturb.

. (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: If you do not see the light, please light the lamp if you are troubled with darkness and you have the 'Lotus'.. (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : Darkness is before you and nothing else.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The floor will be given to you also. Your Party member will speak Mr. Swain. They can also get time to respond.

. (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy-Chairperson, I also remember that the then Home Minister also said that we will issue a White Paper on ISI. All of us remember that. The entire five-year term passed, no White Paper was issued on ISI. Why were you not afraid to name Pakistan then? Why were you not afraid to issue the White Paper on ISI and the role of the ISI? You were in power; you were in Government. What prevented you? The problem is when you are in Opposition, you speak in one tone and when in Government, you speak in an

absolutely different tone. I am surprised that a man as senior as Mr. Malhotra said on the record of this House and I am pained by that. He said, "America gave birth to the Taliban." These were his words. Mr. Deputy-Chairperson, I hope, you strike them out. But, this is what he said. I would like to know from him when they were in Government - on the record of Parliament - did they ever say that? Did any leader say that in Parliament, outside Parliament, to the United States of America and in international forums? Surely, if America gave birth to the Taliban, then that birth to the Taliban was given much earlier, a long time ago. How is it that during the five-year period, when they were in power, they never said any of this? Why is it that they are saying it now when in Opposition? Mr. Malhotra must explain.

It is because we are not doing politics here when having a debate of this serious nature. We are to stand united to fight against terrorism. Ultimately, who was, in fact, compromising with the Taliban at that point in time? Who took the trip to Kandhar? I would like to know. Who went along with Talibanese? Who ultimately set up terrorist organisations which, in fact, resulted in infiltration and killings of hundreds of innocent people in India? You compromised with them; you went with the Talibanese and handed them over to Pakistan.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) .*

SHRI KAPIL SIBAL: Please sit down. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) .*

SHRI KAPIL SIBAL: Have the courage to speak when you have the time! Less said the better about you because you are vanishing in Maharashtra any way.. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of Shri Kapil Sibal.

(Interruptions) .*

SHRI KAPIL SIBAL: Why are you afraid? . (*Interruptions*)

* Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Swain, your party Member will also speak. He can reply to whatever he has said. So, I request you not to disturb the speaker.

Mr. Sibal, I request you also to address the Chair, not him.

SHRI KAPIL SIBAL: I am not addressing him, Sir, not even once.

Sir, I also remember - and this is very important - that the then Home Minister gave a list of 20 terrorists, wrote to Pakistan and said: 'I want these top 20 terrorists who are residing in Pakistan' and the first name in that list was that of Dawood Ibrahim. What happened? Did they achieve any success? Did they raise the issue? Did they tell Pakistan that we would not talk to you till such time you supply at least one of the 20 terrorists? Were steps taken to get Dawood Ibrahim? They knew that he was living in Karachi. They knew the house number. They had intelligence reports. What did they do? Nothing.

They are now blaming the Government for not being vigilant. What happened in Kargil? Infiltrators came in, but there was no information with the Government. Nobody knew about it and ultimately a Minister solemnly said, the Government solemnly said, 'we heard about the infiltration ultimately from the shepherds'. This was the level of vigil that they kept when Pakistani infiltrators and terrorists came into India and occupied our territories and we had to lose almost 800 lives to reclaim our territory. Who was responsible for that? Who kept that vigil? So, before he makes allegations like this, Mr. Malhotra should look at the past, look at the credit that he has for the lack of vigil when their Government was in power.

Sir, I am also very surprised that he has said that they are very happy that help was given during the earthquake and that Rs. 100 crore were given. We are very happy about that. But he has said that the fact of the matter is that that money is now being misused for other purposes and we should monitor it. I do not know

what systems there are in international law to monitor when Governments give money for relief when human tragedies of this magnitude take place. If there is a system in place, certainly we will be more than happy to take the suggestion from Mr. Malhotra. But he did not make the suggestion as to how this was to be done. He made an allegation and because he is in the Opposition he is bound to make the allegation.

Sir, I remember - and this is speaking from the record - that, in fact, a very serious allegation was made by some Members of the British Parliament when money was sent for the Bhuj earthquake victims in Gujarat. It was said that a large part of that money was diverted for terrorist activities within India and we all know ultimately how that money was used. We, in fact, have to fight two battles in this country and this Government is determined to fight both, the terrorists without and the terrorists within. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)** .

SHRI KAPIL SIBAL: Then you should cross over to this side if you were in agreement with me.

Why does walk across the aisle and come over here? . (*Interruptions*)

SHRI UDAY SINGH (PURNEA): This is what we are saying. (*Interruptions*) We are comfortable here.

SHRI KAPIL SIBAL: That is why you cannot be in agreement with me because you are comfortable there. He is right. I really marveled at my learned friend's sense of innocence. He understands everything and pretends not to.

This is the sad part. Money was used. Money was sent for earthquake victims, but money was not used by a political party for earthquake victims. Nothing can be a greater shame in this country.

SHRI LAKSHMAN SINGH (RAJGARH): Can he yield for a moment?

SHRI KAPIL SIBAL: No, I am not yielding.

They say that the Prime Minister of India has never protested against Pakistan. He is a student of politics and a practicing politician. My learned friend

* Not Recorded.

should know that when the Prime Minister met President Bush he said, "there can be no double standards, one for big powers and one for countries like India". He said that openly. When he went to see President Musharaf, he said the same thing that the infrastructure of terrorism in Pakistan has not been dismantled and you must dismantle it. Recently, when he went to SAARC, what did he say? He said, "zero tolerance towards terrorism", and he meant it. Not like their Prime Minister who said, "zero" and became zero.

That is the sad part that when you are in the Opposition, you speak a different language. That is why what happened to them in 2004. That is the result of these kind of speeches and these kind of positions. They told us, when we were asking some questions during the Kargil War, that we are pro-terrorists and what are they doing today. They are playing into the hands of terrorists instead of showing to the world that they are standing united as a country.

They talk about British democracy, Volcker Report, as if Volcker is Golvalker. (*Interruptions*) They can import fascism into this country .(व्यवधान) आप मत घबराइए। मैं असलियत बताना चाहता हूं.(व्यवधान) मैं आपको आपकी असलियत बताना चाहता हूं।.(व्यवधान) They praise British democracy. When Mr. Tony Blair, the Prime Minister of England, talks about terrorist attacks in Delhi, he says, it is an attack against democracy. Well, if the kind of unity that Mr. Tony Blair is showing, they should at least show in this House. Please show that unity in this House. Mr. Tony Blair, who is a not a citizen of India, Prime Minister of another country showing unity towards the Indian Government to fight terrorism. They are citizens of this country, members of a responsible political party, and

they are not showing that unity towards the Government of this country. What is the message that the terrorists will get? It is sad, very sad. It is a shame.

They talk about POTA, without reading POTA. This is the problem, Sir. There have been two amendments made in POTA. Let me make it very clear today. What are those amendments? Number one, that you can get bail after one year in custody. Previously, you could not get bail till the public prosecutor was allowed to oppose it and did not agree. Now, you can actually get bail. Number two, a confession to a police officer is not admissible in evidence. That is all. (*Interruptions*) There is nothing more.

SHRI KHARABELA SWAIN : Yes, that is all. We know that. POTA has been abolished, that is what they say. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing should be recorded, except Shri Kapil Sibal's submission.

(Interruptions) .*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Swain, please take your seat.

SHRI KAPIL SIBAL : Now, these are two amendments that we have made. Under the British law, a confession to a police officer is not admissible evidence. Under the British law, you can get bail immediately. So, if you do not know the British law, why do you criticise? In fact, Mr. Deputy-Speaker, Sir, you know very well that in the debate that took place in Parliament in England recently, they wanted to make the law more stringent. What was the contemplated charge? They wanted to allow the investigating authority to keep the accused in custody for 90 days instead of the regular 30 days. That was rejected by the British Parliament on the ground that it was a violation of human rights. Whereas in India under POTA, you can keep a man in custody for 180 days. Now, if you do not know and you do not again read, what can I do? I cannot help you. . (*Interruptions*)

SHRI KHARABELA SWAIN : I read it. You are not the only person to read it. We also read it. . (*Interruptions*)

SHRI KAPIL SIBAL : I was just trying to inform you in case you do not know. . (*Interruptions*)

* Not Recorded.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kharabela Swain, please sit down.

. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Whoever speaks without my permission shall not go on record.

(Interruptions) .*

SHRI KAPIL SIBAL : POTA represents the most stringent piece of legislation anywhere in the world. It is the most stringent piece of legislation even after the amendment of those two provisions that I have talked about. So, the law is there. The argument was, you have done away with POTA and there is resurrection of terrorism. But when Akshardham was attacked, POTA was in place. When Parliament was attacked, POTA was in place. When the Amarnath pilgrims were attacked, POTA was in place. . (*Interruptions*) What happened? Nothing happened. Action is being taken now. After the investigation, that action will still be taken.

The point that I am making is that POTA or no POTA, terrorism is a global phenomenon and must be dealt with unitedly together as a nation without any politics. This argument of POTA being effective to tackle terrorism is again only a political argument. It is not a nationalistic response by a responsible political party. . (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will be recorded except what Shri Kapil Sibal says.

(Interruptions) .*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Kapil Sibal, I have already said that your speech will only be recorded and nothing else.

SHRI KAPIL SIBAL : Then, my good friend talked about terrorism. He talked about Jehanabad and Nepal, not knowing Jehanabad is in north Bihar and Nepal is 300 kilometres away. I do not understand what the Jahanabad activity

* Not Recorded.

has got to do with Nepal. I can understand the close contact between some political leaders and the North East terrorists. That I can understand. That we all know about. I do not understand the connection between Jehanabad and terrorists somewhere else. That is also a matter of public knowledge. . (*Interruptions*) So, this is not a partisan issue.

Sir, it happened in my constituency, which is why I stand here and speak today.

A lot of people lost their lives. Young children, and innocent women lost their lives for no reason at all. Most of them were looking forward to the celebrations for Diwali and suddenly this human tragedy befell them. I have to say that members of his political party in my constituency were more responsible than Vijay Kumar Malhotraji. I could see the *rehriwalas, dukandars,* neighbours, men and women leaving everything and coming together to save the victims; to help them reach hospitals and not to make incendiary speeches; not to divide the nation. How is it that the BJP workers witnessing the tragedy think differently from Prof. Vijay Kumar Malhotra. Perhaps they are not as political as Malhotra*ji* is. And I pray to God that the citizens of this country, no matter to what political party they belong to, do not inject politics into a debate which requires a national unified response. It is time for us to think about those victims and how we are to take care of them. It is time to think about ways and means of empowering our enforcement authorities to be able to get enough and sufficient information through technology to be able to help in finding out as to whether such attacks in future can be prevented. It is time for us to realize that this can happen to you and me tomorrow as we walk along the streets not knowing as to what our next step will bring for us. In that milieu, in that crowd and in Chhe Tootee Chowk, people of my

constituency were just going about leading their ordinary life, buying sweets not knowing as to what was going to befall them the next moment. Terrorism is a scourge. It has the habit of attacking you and I without any notice under any law. They choose the time, they choose the place and they choose the opportunity. I think that when you are fighting this kind of a battle, you should choose your words before you make a speech of a serious nature in Parliament and try to divide the country. But I know the voice of Prof. Vijay Kumar Malhotra will be drowned in the collective wisdom of our people. It is part of every citizen's conscience in this country. His lone voice will never succeed but the nation will and the Government will.

SHRI NIKHILANANDA SAR (BURDWAN): Mr. Deputy-Speaker, Sir, while taking part on the statement made by our hon. Home Minister on Internal Security, specially in dealing with the terrorist attacks and the naxalites, I heard Prof. Malhotra with rapt attention. But I am sorry to say that he is nicely repaid by Mr. Sibal. What I want to say mainly is that he - hon. Home Minister - outlined the measures that the Government is going to take in dealing with the extremists. We can understand the case of Jammu and Kashmir where the terrorist activities increase or decrease due to some special reasons; cross border terrorism being the reason in most of the cases. But what about Delhi and North Eastern States?

16.00 hrs.

There is no doubt that there are serious lapses. Vigilance is not up to the required mark. Our hon. Minister of Home Affairs cannot avoid his responsibility telling us that the conspiracies are made outside Delhi. That would not serve our purpose. Lapses in the Intelligence Wing led to mishaps. So, more vigilance and a better intelligence set up are required. At the same time, co-operation of the people is earnestly required to deal with the situation.

16.01 hrs. (Shri Devendra Prasad Yadav *in the Chair*)

May I ask what is happening in Manipur, Nagaland, Tripura, and Assam? One officer accompanying us in Kohima made a serious joke. He told us that dual

governments ran in their States: one during day hours and one during the hours after dusk sets in. That is the position in the North-Eastern States. We know that the Government is making compromises with divisive forces and making the problems more critical. Those extremists are using or were using the neighbouring countries, especially Myanmar, Bhutan, and Bangladesh. Myanmar and Bhutan responded to the call made by India and pushed those extremists to our territory but we are sorry that Bangladesh, our friendly neighbouring country, is not behaving in the same manner.

The hon. Minister of Home Affairs was elaborating on the list of organisations but failed to make any comment regarding the functioning of the KLO in northern parts of West Bengal and some parts of Assam. The KLO, which is doing harm in the northern parts of West Bengal has been omitted in his remarks. Apart from these problems, the most important fact is that now for narrow political gains and to win some seats in elections, many parties are having ties with disruptive and divisive forces. The main partner of the UPA also cannot be spared. What happened in Tripura? They joined hands with anti-nationals to win the elections. That was the policy followed by them. Everyone here is aware of the fact that the naxalite movement is not confined only to Bihar or Jharkhand. The disease is spread over many countries. . (*Interruptions*)

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। .(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : गृह राज्य मंत्री गावित जी बैठे हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। .(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Nikhilananda Sar.

(Interruptions) .*

MR. CHAIRMAN: I am on my legs. Please take your seat.

. (*Interruptions*)

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, हाउस में सरकार नहीं है, कोई केबिनेट मंत्री नहीं है।.(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : श्री लाल सिंह जी आप क्या कर रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

* Not Recorded.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. Nothing is going on in the record.

. (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, इतने गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है और सदन में सरकार नहीं है।.(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : गीते जी, आप इतने वरिष्ठ सांसद हैं, कृपया आप बैठ जाइए।

...(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN: Shri Surendra Prakash Goyal, this is not fair. I am on my legs.

. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

. (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, इतने गंभीर विषय पर सदन में चर्चा चल रही है और कोई केबिनेट मिनिस्टर सदन में नहीं है। इस के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए।.(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : यह विषय बहुत ही गंभीर है। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है।

...(<u>व्यवधान</u>)

सभापति महोदय : गोयल जी आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : अगर सरकार गंभीर नहीं है, तो हम लोगों के बैठने का क्या मतलब है। देश की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है, इसलिए निंदा प्रस्ताव लाया जाए। सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, सदन में उपस्थित नहीं है। आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है।.(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record.

(Interruptions) .*

MR. CHAIRMAN: Shri Ansari, please take your seat.

. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on in the record.

(Interruptions) .*

* Not Recorded.

सभापति महोदय : विषय बहुत ही गंभीर है। विषय की गंभीरता का सदन को आभास है। आप सब लोग इससे अवगत हैं। सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। यहां गृह राज्य मंत्री मौजूद हैं।

...(व्यवधान)

SHRI ANANT GANGARAM GEETE : Sir, I am on a point of order. The Cabinet Minister should have been there. . (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Everything is going on as per the schedule. Only one Minister has gone out and another Minister has come in. . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in the record.

(Interruptions) .*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in the record except the speech of Shri Nikhilananda Sar.

(Interruptions) .*

SHRI NIKHILANANDA SAR : The disease has spread in many States, but it is strange . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except the speech of Shri Nikhilananda Sar.

(Interruptions) .*

SHRI NIKHILANANDA SAR : It is strange that there is no naxalite movement in Bengal from where it started. There is no naxalite movement in Bengal now. How did we tackle it there? As you know, Naxalbari is the name of a place in North Bengal. When did it start? It started in 1967. When the Congress misrule in Bengal came to an end, the people had high aspirations and they started the movement. They started grabbing land there. They want to kill the landlords. They started killing constables as if constables were the agents of the landlord and cause of their misery. They burnt the educational institutions. Finally, they started to

* Not Recorded.

bring down the statues of eminent persons of Bengal. This thing went on for some time. Our leaders, mainly the Left leaders, dealt with the situation firmly because it was change of Government only and there was no revolution or total change in the country. We fought a hard battle and sacrificed many of our comrades. They were brutally killed by the naxalites. Finally, we were successful to make them realise that there was change of rulers but not the system. So, at present, there is no naxalite movement in Bengal. It was a very hard task. Finally, the common people lost faith in the naxalite movement.

The Congress Party, instead of denouncing their acts, helped them in whatever way they could. Sir, one word 'Conxal' had come up. During daytime, one person was a Congressman and during night, he turned into a naxalite. As a

result, another breed called 'Conxal' came up. That was the situation during those days. Our friends failed to realise the actual situation and helped them in many ways.

Still, stray incidents are taking place there. In the border areas of Jharkhand, they are adopting hit-and-run policy. They are coming there, creating mischief and flee away into Jharkhand. This is the position there. Such incidents took place in two or three districts of Bengal.

Of course, land movement got momentum during the United Democratic Front, UDF regime and especially in Left Front regime, thousands of acres of land, which were grabbed by landlords through court cases, were distributed to the landless and ample credit was given and minor irrigation was developed. For these reasons, West Bengal, which was a deficit State, turned into a surplus State regarding food production. So, there is no room for naxalite movement in West Bengal at present.

I would request the Home Minister that only better weapons cannot solve the problem. We know what happened in Vietnam. America was on the one side and the poor people of Vietnam were on the other. America had to admit defeat. With country-made goods and ordinary weapons, they actually forced America to quit Vietnam. So, you have to take some measures, and especially the land reform measures, to win over people. If you cannot adopt these measures seriously, the discontent will grow further and you cannot check it.

Disparity between the rich and the poor has grown manifold. While only 10 to 15 per cent of our population is enjoying a good standard of life, there are more than 80 per cent of the people on the other side. This economic disparity between haves and have-nots must be minimised. Progressive measures in land reforms should be initiated immediately in all the States.

At the same time, homestead eviction should be stopped forthwith. Tribal people should not be evicted from the forestlands on which they have been living for centuries. Tribal people are facing a new threat of being evicted from their

forestland. This should be stopped. The Central Government should take initiative, in consultation with all the States, to do these things at least. Otherwise, the commitment of *Bharat Nirman* of the UPA Government will only remain on paper. The Government has to do these things so that the poor people can realise that they are also members of the modern society, civilised society. Otherwise, this disparity would bring the country to disaster.

I hope that the Government would realise the present position and take action immediately in the right direction. They may purchase sophisticated arms and ammunition and technical gadgets. At the same time, simultaneously they have to take up pro-people measures so that discontent among the common people can be removed.

With these words, I conclude.

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल) : सभापति महोदय, यहां जो चर्चा हो रही है, इसमें दो तरह की समस्याएं हैं - एक आतंकवाद से संबंधित है और दूसरी देश के अंदर जो नक्सलवादी या माओइस्ट मूवमेंट चल रहा है, उससे संबंधित है। इन दोनों के अलग होने के कारण निदान अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। आदरणीय मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं। मैं उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। चाहे दिल्ली में बम ब्लास्ट का मामला हो, चाहे काश्मीर में होने वाली आए-दिन आतंकवादी घटनाएं हों, ये सब हमारे पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित हैं। इसमें वहां के लोग भी हैं और कुछ गुमराह लोग यहां के भी हैं, जिन्हें वे ट्रेनिंग देकर यहां भेजते हैं, वे शामिल होते हैं। यह एक ऐसी समस्या है, जिसे कम तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से इसका निराकरण संभव नहीं है। अगर कोई पड़ौसी देश यहां अशांति पैदा करने के लिए अमादा हो तो उसे कम नहीं किया जा

सकता। हां, एक बार ऐसा अवसर आया था, जब हिन्दुस्तान कठोर से कठोर कदम उठा सकता था और दुनिया हमारे खिलाफ नहीं होती। वह मौका था, जब हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट पर आतंकवादियों ने हमला किया था। मुझे याद है, उस वक्त अटल जी ने सारे लीडर्स की मीटिंग प्रधानमंत्री हाउस में बुलाई थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि यही एकमात्र मौका है, जब आतंकवाद की जड़ को खत्म किया जा सकता है और दुनिया हमारे खिलाफ नहीं होगी, वरना आज का युग ऐसा है कि किसी मामूली से देश के खिलाफ भी हम कुछ नहीं कर सकते। इससे दुनिया का रुख बदल जाता है, वातावरण बदल जाता है। असली मौका आप चूक गये। अब दूसरों पर आरोप लगाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। मुझे आश्चर्य हो रहा था, जब आप यह कह रहे थे कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए तो किसी को पता नहीं चला। क्या यह सही नहीं है जो कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि हजारों वर्ग मील जमीन पर कारगिल में कब्जा हो गया और जब एक भेड़ चराने वाले ने बताया, तब आप जान पाये। आप उस वक्त सत्ता में थे। दुनिया का कोई भी अगर दूसरा मुल्क होता तो उस वक्त जो हिन्दुस्तान की सरकार थी, इस तरह की सरकार वहां होती तो एक दिन भी वहां जनता उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसको जबरदस्ती सत्ता से हटा देती, इतना बड़ा अपराध आपकी सरकार के जमाने में हुआ था। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी ज्यादा लापरवाही, इतनी ज्यादा देश की सुरक्षा के प्रति उपेक्षापूर्ण वातावरण या कार्रवाई कभी किसी देश की सरकार ने नहीं किया होगा, जो आपकी सरकार के जमाने में हुआ। जो भी घटनाएं बाद में हुईं और जो अब भी हो रही हैं, अब हम हमला नहीं

कर सकते- स्थिति अब ऐसी बन गई है कि अब नहीं कर सकते। लेकिन बातचीत के जरिये तनाव को कम करके स्थिति को संभाला जा सकता है और स्थिति संभली भी है। ऐसा नहीं है कि कम्पेरेटिवली आतंकवाद कम हुआ है। अभी जो थोड़ा सा कश्मीर में बढ़ा है और यहां जो हुआ है, यहां से होकर हमारे यहां अयोध्या तक पहुंच गया था, उसके लिए आपको इण्टेलीजेंस के नेटवर्क को सुधारने की जरूरत है, खास तौर से जो इलैक्ट्रानिक सर्विलेंस है, गृह मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, काफी आधुनिक उपकरण अब आ चुके हैं। अगर आप बहुत विजिलेंट हों और जब इतने बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमारी प्रापर्टी को नष्ट करते हैं, जनहानि होती है तो अगर बहुत आधुनिक किस्म के उपकरणों को खरीदने के लिए आपको ज्यादा बजट की जरूरत हो तो उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। यह आवश्यक है, किन्तु जो स्थिति बनती जा रही है, उसमें इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

दुनिया में जब से यूनीपोलर व्यवस्था हो गई है, दुनिया में एक ही बड़ी ताकत हो गई है, तब से कोई चैक्स एण्ड बेलैंस वाली स्थिति नहीं रह गई। जिस पर अमेरिका ने हाथ रख दिया, वह थोड़ी सी गड़बड़ी कहीं भी कर सकता है। यह देश कराता ही है। अब अमेरिका की आप सब खिलाफत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा समर्थक जिंदगी भर आपकी ही पार्टी अमेरिका की रही। हम लोग तो हमेशा ही कहते हैं कि यह दबाव में ही दादागिरी कर रहा है। दादागिरी करके हमारे देश की विदेश नीति में भी हस्तक्षेप करने के कारण ही अभी-अभी हम लोगों को और मार्क्सवादियों को और लैफ्ट को, सब को आन्दोलन करना पड़ा। हमारी जाने कब

से जो नीति चली आ रही थी, वह एक दिन में एक झटके में उसने कहा कि आधे घण्टे में जवाब दीजिए, within half an hour या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। ईरान के खिलाफ हमारे प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना है, आधे घण्टे के अन्दर बताइये। कोई दादा ही ऐसी धमकी दे सकता है और हमारी सरकार उस धमकी के आगे झुक गई। लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा देश दुनिया का है, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। हमारी इतनी मैनपावर है, क्या इस तरह से दब जाओगे? कुछ क्यूबा से ही सीख लीजिए। क्यूबा अमेरिका की बिल्कुल नाक के नीचे है, एक घण्टे में मियामी से हवाना नाव से आ जाते हैं, वह तो कभी नहीं दबा। वहां मुश्किल से 1.10 करोड़ की, 1.11 करोड़ की आबादी है, उससे भी कुछ सीखना चाहिए था। हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है, हमारी परम्परा ऐसी नहीं है कि किसी के दबाव में आ जायें और झुक जायें। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से यह काम बड़ा शर्मनाक था। एक बड़ी गलती आपने की और एक गलती की, अब पता नहीं, उस गलती को यह सरकार सुधारेगी या नहीं। लेकिन टैरेरिस्ट्स से निपटने के लिए इलैक्ट्रानिक सर्विलैंस, सीमा पर चौकसी और हर जगह अपनी इंटेलीजेंस को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करना होगा, यही रास्ता है। अब हम किसी देश पर हमला करके उसको दुरुस्त करने की स्थिति में नहीं है। वह मौका हमने गंवा दिया।

जहां तक दूसरे हिस्से का सवाल है, चाहे जहानाबाद में हो, चाहे गिरिडीह में हो या किसी जगह छत्तीसगढ़ में होता है और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र वगैरह में चन्दौली में भी हुआ, यह जो मामला है, यह और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है।

एलटीटीई वालों ने पीडब्ल्यूजी को दक्षिण में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी थी, वे लोग ट्रैनिंग लेकर झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा तक आ गए। झारखण्ड से फिर बिहार तक गए। कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि इसमें दूरी का फर्क नहीं है, माओवादियों ने भी ट्रेनिंग दी है, नेपाल में भी ट्रेनिंग दी गई है। जायसवाल जी, हमारे गृह राज्य मंत्री, जब भी यूपी जाते हैं, उनके मुंह से जो निकलता है, बोलते हैं। उनकी सरकार का शासन है। वहां राष्ट्रपति शासन था, जहानाबाद को घेर लिया गया। पुलिस ने कोई गोली नहीं चलायी। गलती से भी एक गोली चला देते, तो हजार आदमियों में से किसी को तो छर्रे लग ही जाते। बूटा सिंह जी कह रहे हैं कि हमें जानकारी थी। अगर जानकारी थी, तो क्या इंतजाम किए गए? इस आरोप-प्रत्यारोप वाली बात पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। यह देश की समस्या है। लोगों को संसद से उम्मीद है कि इसका कोई न कोई हल निकलेगा, चाहे वह कोई कानून बना कर या व्यवस्था में परिवर्तन करके निकले। हमें इसके मूल में जाना होगा कि आखिर इस तरह के आंदोलन क्यों होते हैं और क्यों लोग हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं?

मैं एक बार हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में आर्टिकल पढ़ रहा था। यह काफी पुरानी बात है। उस समय नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ था। वह आर्टिकल किसी

विद्वान आदमी ने लिखा था, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूं। उस आर्टिकल का टाइटल था 'रूट्स आफ रेवोल्यूशन', उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि संथाल परगना में परम्परा चली आ रही है कि यदि दादा ने कोई कर्ज लिया होगा तो ब्याज में उसका पोता मजदूरी करेगा। इतने बड़े-बड़े इलाके थे, जिसमें एक आदमी के पास इतनी जमीन होती थी कि उसके आस-पास दस-बीस गांव तक भूमिहीन मजदूर ही रहते थे। इस सीमा तक गड़बड़ी थी। यदि किसी भूमिहीन मजदूर के लड़के की शादी होकर आती थी तो उसकी पत्नी पहले दिन उस जमींदार के यहां जाती थी, उसके बाद ही अपने पति के पास जाती थी। एक लड़के से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तमंचे से जमींदार को गोली मार दी। उसने लिखा है कि एक गोली चलाने के बाद ब्याज की दर तीन सौ से घटकर 12 प्रतिशत पर आ गई। This is the route of revolution. लाखों-ऱकरोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास एक ईंच जमीन भी नहीं है। हमारे सोनभद्र में हजारों-लाखों एकड़ जमीन लोग बाप-दादा के जमाने से जोतते चले आ रहे हैं और वे उस पर काबिज हैं, लेकिन वह जमीन उनकी नहीं है। अब उनके बाल-बच्चे निराश हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है। जब भविष्य अंधकारमय है तो वे बंदूक उठा लेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम डॉ. लोहिया के जमाने में नारा दिया करते थे "जो धरती जोते-बोए, वही उसका मालिक होए। " अब सोनभद्र में जो लोग जमीन जोत रहे हैं, उनको जमीन दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम जमीन नहीं दे सकते हैं। वह जंगलात की जमीन है, इसको दिल्ली की सरकार दे दे तो हमारे यहां की समस्या खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आप

लोग ही इसके मालिक हो जाओ। पूरे पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, नक्सलवाद की घटनाएं जो सोनभद्र और चन्दौली में हो रही थीं, सब खत्म हो गईं। सभी ने पंचायत चुनावों में हिस्सा लिया। एक ने भी चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई।

महोदय, लोगों के सामने समस्या बेरोजगारी की है, जमीन की नहीं है। उनके भविष्य में अंधकार है। पीछे देखते हैं तो लोग मजदूरी करते चले आ रहे हैं और आगे भी मजदूरी करनी है। इसका कारण है, सही तरीके से भूमि सुधार नहीं होना। आखिर क्या कारण है कि जिस नक्सलवाड़ी में आंदोलन शुरू हुआ था, वहां पर आंदोलन नहीं फैला? क्या कभी इस पर भी विचार किया गया है? यदि भूमि सुधार सही तरीके से किया जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती। पश्चिम बंगाल में भूमि का सैटलमेन्ट सही तरीके से किया गया। जब पश्चिम बंगाल ने सही कर दिया तो वहां कोई समस्या नहीं नहीं उठ पाई। जहां सबसे ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा निराशा है, वहीं लोगों ने हथियार उठाने का काम किया है। इसलिए मैंने दो दिन पहले या शायद कल ही कहा था कि पुलिस के बल पर आप इस तरह की मूवमैंट्स को कभी नहीं रोक सकते।

माओ-त्से-तुंग ने लिखा था कि जब क्रान्ति होती है तो जमीन हथियार उगलती है। अगर लोग निराश होंगे, तो उठ खड़े होंगे। आपके पास कितनी फोर्स है - कैसे रोक सकते हैं। इसलिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। जमीन का बंटवारा कीजिए। जो इंटीरियर वाले इलाके हैं, स्वयं स्पीकर साहब छत्तीसगढ़ गए थे और कह रहे थे कि वह ऐसा इलाका है जो इनएक्सैसिबल है, जहां पहुंचा ही

नहीं जा सकता। वहां आदिवासी लोग रहते हैं, न कोई स्कूल है, न कोई चीज है, न पढ़ाई-लिखाई है और न ही लोगों के पास जमीन है। वहां स्कूल खोलिए, अगर बच्चा हाथ में बंदूक की जगह कलम ले लेगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, उनको रोजी-रोटी मिलेगी। जमीन का बंटवारा कीजिए। उनको रोजगार देने की कोशिश करें, ट्रेनिंग देने की कोशिश करें, लोगों को मेन धारा में लाने की कोशिश करें। इसे सैंटर और स्टेट मिलकर कर सकते हैं।

आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी है। जितना पैसा आपने बट्टे खाते में डाल दिया, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने कर्ज ले लिया और दिया नहीं, जिन पॉकेट्स में आन्दोलन चल रहे हैं, अगर उतना पैसा उनके डैवलपमैंट में खर्च कर दें तो हिन्दुस्तान से पूरे नक्सलवादी, पीडब्ल्यूजी या माओइस्ट्स मूवमैंट खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक किसान पर दस रुपये बकाया है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और बड़े आदमी पर अगर दस करोड़ रुपये भी बकाया हैं, तो उसे कहा जाता है कि और पैसा ले लो, बाद में दे दीजिए। इस पॉलिसी में बदलाव लाना होगा क्योंकि लोग देखते हैं कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वे उपेक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि जिनके पास है, उन्हें सारी सुविधाएं हैं और जिनके पास नहीं है, उन्हें कोई सुविधा नहीं है। फिर जीवन का कोई मतलब नहीं रहता। जिसके सामने जीवन का कोई अर्थ नहीं है, वह कभी भी अपना जीवन दांव पर लगा सकता है। यही कारण है और इसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी।

यहां सरकार के लोग बैठे हुए हैं। मैंने पहले कहा था कि इंटैलीजैंस नेटवर्क ठीक करें, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलैंस और जितने भी आधुनिकतम उपकरण हैं, वे पुलिस को मुहैया करवाएं। पुलिस बल को आधुनिक हथियार देने की कोशिश करें। एक भी बंदूक ऐसी नहीं है, जो जहानाबाद की जेल में सिपाहियों के पास थी, अगर वे फायर करते तो फायर ही नहीं हो सकता। 303 की आउट-डेटेड बंदूक, जिसे वे कभी चलाते नहीं हैं, अगर उसे चलाने की कोशिश करते हैं तो मिस हो जाती है, कभी चलती नहीं है। यह स्थिति है। पुलिस बल को माडर्नाइज़ करने की जरूरत है, सर्विलैंस की जरूरत है।

हमने बहुत पहले कहा था कि कम्प्यूटर्स दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लाने वाले हैं। अब अगर मैं यह कहूं तो आप कहेंगे कि यह तो दकियानूसी है, पुरानी बात कहने वाला है। कम्प्यूटर्स ने बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है। जहां कम्प्यूटर्स की जरूरत नहीं है, पिछड़े इलाके हैं, वहां लोगों को रोजगार मिल सकता है, वहां रोजगार देने की कोशिश करें, लेकिन आप देश के बजट का 16 फीसदी आईटी पर और एक फीसदी एग्रीकल्चर पर लगाने में लगे हुए हैं। सरकारों का सोचने, समझने और काम करने का यह जो तरीका है, अगर इसमें मूलभूत परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो जितनी बहस कर लें, हम इसका कोई निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वे आंध्र प्रदेश से लेकर झारखंड तक हों, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या दूसरे इलाके में हों, इन सारी घटनाओं की जड़ में जाकर उसके कारणों को समाप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि देश के जिन हिस्सों में सम्पन्नता है, वहां ऐसी

घटनाएं होती ही नहीं। एक राज्य में यदि कुछ जिले सम्पन्न हैं तो वहां इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जहां गरीबी है वहीं यह समस्या है। गरीबी, बेरोजगारी और असली चीज है भूमि का बंटवारा। जिस दिन लोग भूमि के मालिक हो जायेंगे, उनके लड़के पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे तब उनका भी सपना होगा कि हमारा लड़का भी बड़ा होकर नौकरी पा सकता है, पुलिस का सिपाही बन सकता है। .(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आप सुझाव दीजिए। .(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं सुझाव ही दे रहा हूं कि जमीन का बंटवारा कीजिए। अब हम कैसे कर सकते हैं ? .(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : आप बता नहीं रहे हैं। .(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं बता रहा हूं। .(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : यहां सब नेता बोलते हैं। सब पार्टियों के लोग बोलते हैं। उनमें से कई लोगों का तो स्वर्गवास भी हो चुका है। लेकिन इसका इलाज क्या है ? आपको बोलना चाहिए कि सारी पोलिटिकल पार्टी के नेताओं को बैठकर देश की एग्रीक्लचर लैंड को टेकओवर करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जब इस पर सारे लोग कायम होंगे तब लैंड का डिक्टेटर कौन होगा ? .(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : यही नहीं, पैसा भी जब्त होना चाहिए। नेताओं के पैसे को जब्त करके उसे भी बांटा जाये। .(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : पैसा भी जब्त होना चाहिए। आप सब बोलिये। क्या यहां भाषण देने से कुछ होगा ? .(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Prof. Ram Gopal Yadav says.

(Interruptions) .*

सभापति महोदय : मानवेन्द्र जी, आपका रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है इसलिए आप बैठ जाइये।

...(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. राम गोपाल यादव : लालू जी ने जो सुझाव दिया है, हमने तो उत्तर प्रदेश में भूमि सेना बनाई हुई है। .(<u>व्यवधान</u>)

श्री लालू प्रसाद : आप पूरे देश की बात कीजिए। .(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. राम गोपाल यादव : पूरे देश की बात तो यहां बैठे हुए लोग कर सकते हैं। पूरे देश में हर जगह यह चीज नहीं है। जिस राज्य में बहुत ज्यादा गरीबी या विषमता है वहीं ऐसा है। इसलिए वहां यह करना पड़ेगा। .(<u>व्यवधान</u>)

* Not Recorded.

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए क्योंकि आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. राम गोपाल यादव : यह बंटवारा क्यों नहीं हो सकता ? आप हमें बना दीजिए, क्योंकि हमने अपने यहां इसे लागू कर दिया है। हम दिल्ली सरकार को लिखकर भेज रहे हैं कि सोनभद्र वाली जमीन हमें दे दें। उस जमीन को जो लोग जोत रहे हैं, वे ही उसके मालिक होंगे। आप इजाजत देते तो यह हो जाता लेकिन

वह जमीन दिल्ली सरकार के हाथ में है। जो बंजर भूमि पड़ी हुई है, उसमें गवर्नमैंट पैसा खर्च कर रही है। सरकार पैसा उन्हीं लोगों को देगी, जो उस जमीन को जोतेंगे, बोयेंगे। जब वे भूमि के लायक हो जायेंगे तब वे उसके मालिक हो जायेंगे। अब यह हो रहा है या नहीं ? .(व्यवधान) हम यह कर रहे हैं। लालू जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह काम राज्य सरकारों को ही करना होगा। राज्य सरकारों के काम करने में अगर बाधा आयेगी तो केन्द्र को उसमें सहयोग करना होगा। यही रास्ता है। This is my submission.

सभापति महोदय : अब आप कन्कलूड कीजिए।

...(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव : इन्हीं शब्दों के साथ मै अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : सभापति जी, लगभग हर सत्र में हम आतंकवाद पर सदन में बहस करते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि यह हर सत्र का विषय हो गया है। इसका असर न सरकार पर हो रहा है और न ही आतंकवादियों पर हो रहा है। मैं यह बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। वैसे मेरी आज बोलने की इच्छा भी नहीं थी। खाली एक ही मुद्दा है जिसको मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। जो दो बयान माननीय गृह मंत्री जी ने दिये, उन्होंने कुल चार बयान दिये, जिनमें से दो नक्सलवादी गतिविधियों पर उनके बयान हैं और दो बयान सीमापार आतंकवादियों के जरिए चलाई गई आतंकवादी घटनाओं के बारे में हैं। एक बयान 29 अक्तूबर को जो दिल्ली में

पहाड़गंज, सरोजनी नगर मार्केट और कालका जी में लगातार तीन बम विस्फोट, एक के बाद एक बम विस्फोट हुए, उसके संबंध में है। दूसरा बयान जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी हिंसाचार हुआ, उसके संदर्भ में है। दोनों बयानों में एक समानता है जिसकी ओर मैं सरकार और इस सदन दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, उस संबंध में गृह मंत्री जी कहते हैं कि "मामले की जांच-पड़ताल के दौरान यह पता चला है कि दिल्ली में बम-विस्फोट करने की साजिश विदेश स्थित उग्रवादी संगठन द्वारा रची गई थी।" यह गृह मंत्री जी का बयान है। उन्होंने कहा कि यह साजिश विदेश स्थित उग्रवादी संगठन द्वारा रची हुई साजिश है। जब गृह मंत्री जी इसे विदेश स्थित उग्रवादी संगठन कहते हैं तो मुझे लगता है कि यह इशारा पाकिस्तान की तरफ है। जम्मू-कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उसके ऊपर जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया है, उस बयान का एक पैराग्राफ मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा- "राज्य में राजनैतिक सत्ता के परिवर्तन के बाद, आम तौर पर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति उस समय भी देखी गई थी, जब पूर्व सरकार ने नवम्बर, 2002 में सत्ता संभाली थी। आतंकवादियों ने नवम्बर 2002 से जनवरी 2003 के बीच दुखभरी बड़ी वारदातें कीं जिनमें रघुनाथ मंदिर पर किया गया आत्मघाती हमला शामिल है।" "संकेतात्मक हिंसा में वृद्धि का दूसरा कारण यह है कि आतंकवादी गुट क्या यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हाल के भूकम्प के बावजूद भी उनकी मारक क्षमता और आतंक फैलाने का उनका संकल्प समाप्त नहीं हुआ

है। यद्यपि सीमापार बाड़ लगाने और घुसपैठ रोकने के कारण घुसपैठियों की संख्या में कमी आई है लेकिन निश्चित रूप से घुसपैठ जारी है। सीमा के उस पार से आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता भी जारी है।" यह अलग-अलग गृह मंत्री जी के बयान हैं। वे दोनों बयान यही दर्शाते हैं कि ये आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं, इन सारी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान है।

महोदय, जब यहां विजय कुमार मल्होत्रा जी अपनी कह रहे थे, तब उनके कहने को तोड़-मरोड़कर यहां पर रखा गया और फिर यह कहा जाए कि विजय कुमार मल्होत्रा जी सुझाव देना चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना चाहिए। मैं हिन्दुस्तान के इतिहास को यहां दोहराना चाहूंगा। आप मुझसे सहमत होंगे, सारा सदन भी इस बात से सहमत होगा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजा-महाराजाओं के जमाने से भी आप अपने इतिहास को देखें तो निश्चित रूप से आप इस बात से सहमत होंगे कि हिन्दुस्तान ने आज तक कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमारे ऊपर आक्रमण किया मुगलों ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया ब्रिटिशर्स ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया फ्रेंच लोगों ने, हमारे ऊपर आक्रमण किया पुर्तगीजों ने, कई देशों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए । यदि हम पुराना इतिहास न दोहराएं और आजादी के बाद का इतिहास ही देखें, तो चाहे पाकिस्तान के साथ हुए चार युद्ध हों, जिनमें कारगिल भी शामिल है, या चीन के साथ हुआ हमारा युद्ध हो, इन सभी युद्धों में या तो पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया है या फिर चीन ने हम पर आक्रमण किया है। कारगिल में भी पाकिस्तान ने ही

आक्रमण किया था, जिस आक्रमण से हमने कारगिल को मुक्ति दी, अपनी भूमि को मुक्त कराया। इसलिए हमारा इतिहास इस बात का सबूत है कि हिन्दुस्तान ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है और न ही इस सदन से कभी भी किसी ने कहा है कि पाकिस्तान पर हम आक्रमण करें। पाकिस्तान पर आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। हम यह नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हम यह भी नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान की जनता हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान पर पिछले कई वर्षों से राज कर रहे हैं, वे हमेशा हिन्दुस्तान के दुश्मन रहे हैं, वे हमेशा हिन्दुस्तान के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने हमेशा हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने की कोशिश की है और हर आक्रमण का हमने मुकाबला धीरज के साथ किया है और हर आक्रमण को, चाहे वह पाकिस्तान का हो या चीन का हो, हमने उसे परास्त किया है। जैसा माननीय सदस्य श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा, आज ऐसा समय आ गया है कि हम किसी पर भी आक्रमण नहीं कर सकते। आज का वातावरण इतना बदल गया है, दुनिया इतनी छोटी हो गयी है कि यदि कोई भी गलत कदम उठता है तो सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो सकती है। आज का समय ऐसा नहीं है कि कोई अपनी बात को युद्ध के जरिए या लड़ाई के जरिए किसी के सिर पर थोप सके। लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है,तब हमें किसी भी तरह राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई

समझौता नहीं करना चाहिए। हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, हमारी सीमा की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें ऐसी मानसिकता बनाने की आवश्यकता है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहूंगा - जब हम सरकार में थे, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब आतंकवाद बढ़ा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए अटल जी ने यह घोषणा की कि हम जम्मू-कश्मीर में अपनी सीमाओं के आस-पास स्थित जितने भी आतंकवादी हैं, उनकी कॉम्बिंग करके, उनको ढूंढकर खत्म किया जाएगा। जब उनकी और उनको खत्म करने का ऑपरेशन शुरू हुआ और इस ऑपरेशन के समय ही रमजान का महीना आ गया, तब अटल जी ने एकतरफा सीजफायर घोषित किया और कहा कि रमजान के महीने में हम हथियार नहीं चलाएंगे। जब इस बात पर सदन में चर्चा हुई, उस समय हमने इस कदम का विरोध किया था। हमने इसलिए विरोध नहीं किया था कि रमजान से हमारा कोई विरोध है। चाहे इस्लाम धर्म हो या कोई अन्य धर्म, अगर वे अपने त्यौहार मनाते हैं तो उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन रमजान के नाम पर सीजफायर की घोषणा की गयी और उसी समय रमजान के महीने में सबसे ज्यादा खून की नदियां आतंकवादियों ने बहाईं। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री ने रमजान का सम्मान किया, ऑनर दिया, लेकिन आतंकवादियों का न कोई धर्म है, न मजहब है और न ही कोई त्यौहार है। उनके दिमाग में तो सिर्फ खून सवार है। इसलिए रमजान के

महीने में भी उन्होंने खून की नदियां बहाईं। जवान मारे गए, सिविलियन मारे गए, बूढ़े और बच्चे मारे गए। तब भी हमने सरकार में होते हुए विरोध किया था और कहा था कि आतंकवादी मानवता नहीं समझते हैं। आतंकवादी हर दिन मानवता की हत्या कर रहे हैं और हम मानवता की बातें कर रहे हैं। जो आतंकवाद कल तक जम्मू-कश्मीर तक सीमित था, आज वह देश के कोने-कोने में फैल गया है। हर राज्य में बम विस्फोट हो रहे हैं और कोई बड़ा शहर नहीं बचा है, इसलिए यह विषय मानवता का नहीं है। आतंकवादियों को उनके ही तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार को इस तरह की मानसिकता बनाने की जरूरत है, भले ही वह सरकार एनडीए की हो, यूपीए की हो या किसी भी राजनीतिक दल की हो। सरकार को इस निर्णय पर आने और आतंकवादियों के खिलाफ कठोरता अपनाने की आवश्यकता है। यह संदेश आतंकवादियों को देने की आवश्यकता है कि भारत की सरकार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मानसिकता को हम कैसे आतंकवादियों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है कि हमें सख्त कानून की आवश्यकता है।

जब लोक सभा में पोटा बिल पारित हुआ, तो राज्य सभा में वह पास नहीं हो सका। उसके बाद संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर पोटा बिल पास कराया गया। मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं, क्योंकि जब गृह मंत्री जी बयान देते हैं कि हर हमले में पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए पोटा जैसा कानून आवश्यक है।

हाल ही में कश्मीर इलाके में भूकम्प आया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय सबसे पहले हमारी सेना ने पाकिस्तान से यह इजाजत मांगी कि हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, हम जीवितों को बचाना चाहते हैं और लाशों को ढोना चाहते हैं, आप हमें यहां आने दें। लेकिन मुशर्रफ साहब ने हमारे हैलिकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत नहीं दी। वह हमसे मदद तो चाहते हैं धन के रूप में या अनाज के रूप में, लेकिन हमारे सिपाही वहां नहीं आने देना चाहते। इसका क्या कारण था, यह हमें मालूम नहीं है। कुछ समय बाद कश्मीर में कुछ जगहों पर सीमाएं खोली गईं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मानवता के नाते वहां भी हम हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहां के रूलर्स इस बात को नहीं मानते।

सभापति महोदय, मैं विषय से अलग नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को कड़ा रुख अपनाने की मानसिकता बनानी चाहिए। उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। इन्हें हम आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते, आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन एक कानून तो बनाया जा सकता है। जो ऐसा पोटा कानून था, उसे आपने समाप्त कर दिया। पोटा किसके खिलाफ था, जब हमारी संसद पर हमला हुआ, उसके बाद बहस हुई, तब भी मैंने यह कहा था कि जो पांच पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं, वे हमारी संसद में कैसे आए। किन लोगों ने उन्हें पनाह दी। .(व्यवधान) मान लो कि इंटैलिजेंस फैल्योर था लेकिन यह किन लोगों के जरिये हुआ। ये कोई हवा में से नहीं टपके। ये हमारी धरती से ही दिल्ली

पहुंचे, किसी के मकान में रहे और वर्षों तक रहे। किन लोगों ने इन्हें पनाह दी? क्या वे भी सारी घटना के जिम्मेदार नहीं हैं, क्या वे लोग भी उतने ही दोषी नहीं हैं? लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को सजा दे सकते हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं जिन्होंने इन्हें धन दिया, रहने के लिए मकान दिया, घूमने के लिए गाड़ियां दीं और आरडीएक्स लाने में मदद की। मदद करने वाले सारे भारतीय थे। पाकिस्तान के तो केवल पांच ही लोग थे, बाकी मदद करने वाले सारे भारतीय थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई आप उनके ऊपर कर रहे हैं? उनके मन में आपका क्या डर है? मुम्बई में बम विस्फोट हुआ, लेकिन विस्फोट करने वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सरकार का उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उनके मन में सरकार का डर होना चाहिए लेकिन डर तभी होता है जब कानून सख्त होता है।

आप दुबई में चोरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डर है कि चोरी करने पर हाथ काट दिये जाएंगे। दुबई में महिला की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकते हैं क्योंकि सब के सामने गोली मार दी जाएगी। वहां पर सरकार का डर है, कानून का डर है लेकिन वह हिम्मत भी हमारी सरकार में नहीं है। एक सरकार सख्ती बरतती है दूसरी सरकार उस सख्ती को खत्म कर देती है। इससे आतंकवादियों को क्या मैसेज जा रहा है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं।

कुँवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : आपकी सरकार को क्या डर था?

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैंने तो अपनी सरकार की भी बात की है। मैं किसी सरकार के समर्थन में नहीं कह रहा हूं।

MR. CHAIRMAN : Nothing will be recorded except Shri Anant Geete's speech.

(Interruptions) .*

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

(Interruptions) .*

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats.

श्री अनंत गंगाराम गीते : अगर सरकार का डर नहीं होगा तो आतंकवादी हमसे क्यों डरेंगे। जब सरकार से, कानून से उनको कोई खतरा नहीं है तो वे सरकार से क्यों डरेंगे। मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार की ओर से कड़े कानून नहीं बनाए जाएंगे और सरकार अपनी मानसिकता का सबूत नहीं देगी और यह साबित नहीं करेगी कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ डटकर लड़ेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान पर हमला करने की हमें जरूरत नहीं है बल्कि हमें जरूरत है कि सरकार अपनी दृढ़ मानसिकता का परिचय दे कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

* Not Recorded.

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति जी, आज नियम 193 के तहत गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर इस सदन में बहस हो रही है। महोदय, हमारे गृह राज्य मंत्री जी ने सभापटल पर जो अपना बयान प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ने का मौका मुझे मिला।

महोदय, 18 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में, 29 अक्टूबर को दिल्ली में, 11 नवम्बर को झारखंड में गिरिडीह के होमगार्ड पुलिस लाइन में और 13 नवम्बर को बिहार के जहानाबाद पुलिस लाइन एवं जेल पर हमले की चर्चा हो रही है। हम

जहानाबाद क्षेत्र से निर्वाचित होकर आते हैं। ये घटनाएं कोई शुरूआत नहीं हैं बल्कि इस प्रकार की घटनाएं अतीत में, पहले भी घटित होती रही हैं।

17.00 hrs.

परंतु इन घटनाओं को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? हम जो सदन में बैठे हुए लोग हैं, क्या घटना घटने के बाद महज उस पर चर्चा करने के बाद सो जाते हैं या हम आपसी सहमति से इन घटनाओं को रोकने में जैसे हमारे देश की सुरक्षा पर आक्रमण होता है, देश पर आक्रमण होता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम सब मिल कर दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करते हैं और आज संकट की घड़ी में लगातार एक के बाद एक ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए आम सहमति की आवश्यकता है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं , एनडीए के माननीय सदस्य बोल रहे थे और रचनात्मक सुझाव देने के बजाए प्रधानमंत्री जी पर छींटाकशी एवं उनकी आलोचना कर रहे थे, लेकिन उनके अपने कार्यकाल का स्मरण करना होगा, इस संसद में हमला होने वाला था, हमारे जो बहादुर प्रहरी संसद में थे उनकी बहादुरी के कारण उनकी सतर्कता के कारण यह संसद बची और संसद के लोग बचे, आज अगर वे आलोचना करें तो मैं कहूंगा कि आलोचना से काम चलने वाला नहीं है।

दिल्ली में जो घटनाएं घटी थीं, उनमें काफी लोग मारे गए थे। घटनाएं ऐसी जगहों पर एक साथ घटीं, जहां काफी भीड़-भाड़ थी, इसी प्रकार से आगे की घटनाएं भी हुई। इन घटनाओं के संबंध में कहा गया कि इनमें बाहरी

आतंकवादियों का हाथ है। हमारे सामने झारखंड और बिहार की घटनाएं है। उसमें जो आतंकवादी हैं उनके संबंध में कहा जा रहा है कि वहां पर पीडब्ल्युजी और माओवादी लोग हैं। ये कहां के लोग हैं, क्या सरकार ने पता लगाने की कोशिश की? ये माओवादी आंध्रप्रदेश से सक्रियता शुरू करते हैं, उड़ीसा में आते हैं, छत्तीसगढ़ में आते हैं, झारखंड में आते हैं, बिहार में आते हैं, ये सभी नेपाल से क्रास करते हैं। बिहार होकर झारखंड सहित तमाम इलाकों में ये विचरण करते हैं और फिर घटना को अंजाम देने का काम करते हैं। लेकिन हमारा भी कोई दायित्व है, शासन और प्रशासन का कोई दायित्व है, खासतौर पर जहानाबाद की घटना के बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गृहमंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि तीन-चार सौ आतंकवादी जहानाबाद में प्रवेश कर गए। महोदय, यह सच्चाई नहीं है। मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं और घटना के दिन सुबह मैं वहां पहुंचा, वहां के प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों ने बताया कि जहानाबाद शहर पर साढ़े 7 बजे से 8 बजे तक पूरी तरह से आतंकवादियों का कब्जा हो गया था और उनकी संख्या तीन-चार सौ नहीं, बल्कि 2 हजार थी, जो हथियारों से लैस थे, राइफलों से लैस थे, बमों से भी लैस थे। वे आतंकवादी सीधे-सीधे सरकार और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे थे। वे जीप में बैठकर माइक से प्रचार कर रहे थे कि यदि कोई आदमी सड़क पर बाहर निकला, तो उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। मैंने वहां देखा है, ऐसी मुख्य सड़क पर जहां कचहरी चौक है, जहां न्यायालय है, उस चौक पर बहुत बड़ा बम रखा हुआ है। वह भीड़ का इलाका है, लोग आवागमन कर रहे

हैं। उससे आगे मुख्य सड़क पर भी बम रखा हुआ था, पुलिस लाइन के आगे बम रखा हुआ था, इन सारी जगहों पर कैसे लोग पहुंचे? पब्लिक के डर से, उनके आहवान से, उनकी घोषणा से लोग नहीं निकल पाए, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? ऐसा कहा गया कि पुलिस बहादुरी के साथ लड़ी। महोदय, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जहानाबाद जैसी जगह में यह कोई नयी घटना नहीं है।, उसी जहानाबाद में आपको स्मरण होगा कि बाथे कांड हुआ, उसी जहानाबाद में सिनारी हुआ, उसी जहानाबाद में मियांपुर हुआ, उसी जहानाबाद में नौन्ही और नगवाँ हुआ, उसी जहानाबाद में परसविघहा और डोहिया कांड भी हुआ है। ऐसे संवेदनशील इलाके से मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि देश में शासन केन्द्र सरकार का है या चुनाव आयोग का शासन है? सच्चाई है कि पूरी की पूरी पुलिस को दूसरी जगह चुनाव में लगा दिया गया था। नक्सली ताक में थे। वे खोज कर रहे थे कि वहां की क्या स्थिति है क्योंकि जहानाबाद जेल में उनके दल के बड़े नेता बंद थे। उन्होंने मौका पाकर सारी स्थिति की जानकारी ले ली कि वहां पुलिस बल नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक साथ हमला करने का काम किया। सच्चाई जानने की जरूरत है। खुद बिहार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी तीनों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इस घटना की जानकारी पहले से थी। ऐसी जानकारी 2-3 दिन पहले से नहीं बल्कि 4-5 माह से थी कि जहानाबाद के कई प्रमुख जगहों में आतंकवादियों द्वारा पुलिस लाइन और सरकारी भवन पर हमला हो सकता है। इतना असतर्कता क्यों बरती गई? वहां से पुलिस बल क्यों हटाया गया? यह एक जांच का विषय है। गृह मंत्री यहां नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस

मामले की जांच होनी चाहिए कि वाकई वहां कितनी पुलिस थी? मैं रिपोर्ट में लिखी गलत बात बताना चाहता हूं। वहां मात्र आठ पुलिस वाले थे। वहां 6 महीने के पहले से ऐसी स्थिति थी तो सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? आप पुलिस लाइन को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। वहां चार दीवारी भी नहीं थी। वहां ऊपर कहीं भाले और कांटे नहीं लगे थे। अभी कुछ दिन पहले वहां हल्के-फुल्के कांटों को लगाया गया है जिस में कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर घुस सकता है। उस पुलिस लाइन में भारी शस्त्र रखे थे। वहां मैगजीन और शस्त्रागार थे। संयोग से वहां से कोई सामान लूटा नहीं जा सका।

इसी तरह जेल की बात है। ऐसी जगह जेल स्थित है जिस के आसपास कोई सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं है। बरसों से बात हो रही है कि जेल को और कहीं शिफ्ट किया जाए और उसे सुदृढ़ व मजबूत बनाया जाए। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी शेप को बदला जाए लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जेल की यह स्थिति है कि वहां 15-16 फीट की दो कच्चे बांस की सीढ़ियां थीं। उस सीढ़ी से नक्सलवादी अन्दर घुस गए। जेल के अन्दर सिपाही आठ की संख्या में थे। उनके पास हथियार ज्यादा थे। सारे के सारे हथियार नक्सलियों ने लूट लिए। उन्होंने कैदियों को धमका कर और भय पैदा करके भगाने का काम किया। उसी जेल में अजय कालू बंद था। बिहार के सभी लोग जानते हैं कि अजय कालू पीडबल्यूजी का और माओवादियों का मुख्य नेता है। मकसद उसी अजय कालू को छुड़ाने का था। वे लोग ये सब करने के बाद रफू-चक्कर हो गए। ऐसी घटना के बाद पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होती तो जरूर उनका पीछा करती और उन

आतंकवादियों को चेज करती। यह नौ बजे की घटना है। रात भर कोई किसी की सुध लेने वाला नहीं था। वहां लोग किस हालत में थे, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। यह बहुत दूर की बात रही। यदि उनका आधे घंटे, एक घंटे या दो घंटे के बाद भी पीछा करते तो 2-4-5 किलोमीटर के अन्दर इतनी भारी संख्या में नक्सली लोग पकड़े जाते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर, इसके पीछे क्या कारण हैं? कारण बहुत बड़ा है। उस इलाके में रणबीर सेना भी है, उस इलाके में भूमि सेना भी है। इन सेनाओं और माओवादी संगठनों का आपस में हमेशा टकराव होता रहता है। जब किसी तरफ से निर्दोष व्यक्ति को कोई मारता है तो उस पर प्रतिक्रिया होती है और बदला लेने की भावना से वे एक-दूसरे को मारते हैं। वे चार को मारते हैं तो दूसरा दो को मारता है और यही चलता रहता है। वहां बहुत सतर्कता से काम लिया जाना चाहिए क्योंकि उसी जेल में रणवीर सेना के लोग भी हैं, उसी जेल में माओवादी लोग भी हैं। इसी तरह से एक ही जगह दोनों तरफ के लोग हैं। तब वहां दोनों तरफ के लोग जेल में दरबार लगाते थे और दोनों के समर्थक जेल में जाते थे। वे लोग इस स्थिति से अवगत थे और ऐसी घटना घट गई। क्या इससे ज्यादा दर्दनाक घटना हो सकती है? क्या इससे बड़ी घटना हो सकती है? झारखंड में घटना हुई, झारखंड में भी पुलिस लाईन को लूट लिया गया। पुलिस लाईन के प्रशिक्षण केन्द्र में इतने हथियारों के रहते, इतने पुलिस बल के रहते उसे क्यों लूट लिया गया? ये झारखंड की बात कह रहे हैं। जब से झारखंड बना है, बी.जे.पी की सरकार बनी है, झारखंड में उग्रवाद और बढ़ गया है। ये बिहार की बात कहते हैं। मैं मानता हूं कि वहां की सरकार विफल रही है, प्रशासन

विफल रहा है जबकि वहां राष्ट्रपति शासन था। इस तरह से कैसे काम चलेगा? जबकि आपकी पुलिस लाईन लूटी जा रही है, सरकारी भवन लूटा जा रहा है। पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है तो आम नागरिक की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज भी झारखंड और बिहार के उन इलाकों में भय का वातावरण है। यह कोई नई घटना नहीं है। आपको स्मरण होगा इससे पहले भी मोतीहारी जिले के मधुबना इलाके में 23 जून को भयंकर घटना घटी। वहां एक ही बार में सात स्थानों को लूटा गया। वहां की पुलिस लाईन, थानें और चौकियों पर ही नहीं यहां तक कि माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह के आवास पर भी हमला हुआ। लेकिन कहां कोई आतंकवादी पकड़ा गया? गलत रिपोर्ट दी गई कि आतंकवादी को पकड़ लिया गया। लेकिन जो वास्तव में आतंकवादी हैं, जिन्होंने आतंक फैलाया है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाता है।

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये सब बातें और आतंकवादी घटनाएं दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि धीरे-धीरे पूरे हिन्दुस्तान में बढ़ गई हैं। हम पहले सुनते थे कि आजादी के तीसरे दशक में बंगाल के नोआखली से आतंकवादियों का जन्म हुआ। उसके बाद वे लोग आगे बढ़े लेकिन आज वहां यानि बंगाल में आतंकवादी नाम की कोई चीज नहीं है। हमें इस बात की भी जानकारी लेनी पड़ेगी और उसका उपाय ढूढ़ना पड़ेगा। मेरे विचार से जिस तरह से आतंकवादी किसी घटना को अंजाम देने के लिए दृढ़संकल्पित होते हैं उसी तरह से सरकार को संकल्प लेना चाहिए कि दृढ़ता के साथ आतंकवादियों

को समाप्त करेंगे और जो आतंकवाद में विश्वास रखने वाले हैं, जो हिंसा मे विश्वास रखने वाले हैं, उनका खात्मा करेंगे।

मेरा विचार और सुझाव है कि जो प्रशासनिक तंत्र है, इस प्रशासनिक तंत्र को भी सुदृढ करना पड़ेगा। ऐसे इलाकों में ईमानदार, कर्मठ और सुयोग्य पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा जो पारदर्शिता ला सकें। इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे देश में जो आतंकवाद फैल रहा है कहीं न कहीं उसकी वजह सामाजिक और आर्थिक कारण भी है। आर्थिक कारण यह है कि जिनके पास पैसा है, उनके पास काफी पैसा है और जिनके पास जमीन है, उनके पास काफी जमीन है लेकिन जो गरीब लोग हैं, वे भूखे मर रहे हैं। उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सीलिंग एक्ट बना हुआ है, उस सीलिंग एक्ट को तीव्रता से, कारगर ढंग से और कठोरता से लागू करने की जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि विकास की बात कही जाती है। हमारी सरकार भी कहती है कि इतने हजार करोड़ रुपए और इतने लाख करोड़ रुपए हमने भेजे हैं। किस के लिये भेजे और कहां पहुंचे? आपने गरीबों के लिये भेजे थे ताकि उन गरीबों को उसका लाभ मिल सके लेकिन पहुंचे नहीं - इसकी भी जांच होनी चाहिये।

सभापति महोदय, हमें उन गरीबों को शिक्षित करना होगा, उनके टोले में विद्यालय खोलना होगा, उनके गांवों में पेयजल की व्यवस्था करनी होगी, उनके टोले में आने जाने के लिये सड़क की व्यवस्था करनी होगी। अगर ऐसे कामों में

सरकार और विपक्ष सभी लोग सहमति करेंगे तो इनफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ेगा। नेपाल से आध्र प्रदेश तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है, झारखंड से बिहार, उड़ीसा से झारखंड और आध्र प्रदेश से झारखंड तक कोई बॉर्डर रोड नहीं है। ऐसे स्थानों पर क्रॉस करना और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिये आसानी होती है। ऐसी जगहों पर बॉर्डर रोड बनानी पड़ेगी और उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। यह सब को मालूम है कि किसी भी घटना को तभी रोका जा सकता है जब उस घटना का पूर्वाभास होगा। हमारी खुफियातंत्र को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी अत्याधुनिक संयंत्र एवं हथियारों से लैस करना होगा।

सभापति महोदय, आज थानों की क्या स्थिति है? उनके पास अपना भवन नहीं है, अपना फोन नहीं है, अगर है भी तो फोन बिल न अदा कर पाने की हालत में फोन कटा रहता है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन पर अपनी जीप तक नहीं होती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुये ऐसी जगहों पर फंडिंग की जरूरत है। सरकार सम विकास योजनाओं की समीक्षा करेगी लेकिन कहीं काम नहीं हो रहा है। इसलिये ऐसी जगहों पर विशेष फंड्स देकर गरीबों के साथ न्याय करने की जरूरत है। अगर उनके साथ न्याय होगा तो उनका झुकाव आतंकवादियों की तरफ नहीं होगा और वे उनके बहकावे में नहीं आ सकते।

*DR RATTAN SINGH AJNALA (TARAN TARAN): Mr Chairman Sir, I am thankful to you for allowing me this opportunity to speak on a very important issue.

MR CHAIRMAN: Have you given a notice to speak in Punjabi?

DR RATTAN SINGH AJNALA: I have given the notice.

MR CHAIRMAN: We have to make arrangement for translation.

DR RATTAN SINGH AJNALA: I have given the notice.

What are the reasons for these violent movements? Poverty, illiteracy and the Governments that perpetrate injustice on people, give rise to militancy.

17.23 hrs. (Shri Varkala Radhakrishnan in the Chair)

Mr Chairman Sir, in Punjab, militancy and terrorism were fuelled by Congress party. Militancy started in Punjab around 1978 and thousands of people lost their lives in terrorism related violence. Even one of our party presidents was assassinated by terrorists. Rajeev-Longoval accord was signed but it was not implemented. The non-implementation of this accord further boosted the ranks of terrorists. Punjab suffered due to this. At present, terrorism is a scourge that plagues not only India but the whole world. Earlier, the two superpowers USA and Soviet Union wanted to establish their hegemony in the entire world. USA trained ultras like Laden in Afghanistan. But a time came when these terrorists turned against the US like Frankenstein monster. Then the USA realised that terrorism is a menace. In Punjab, there was unemployment, poverty and illiteracy. The young men were swayed by sentiments and took to guns. The Pakistani intelligence agency ISI fished in troubled waters. It trained the militants. Punjab suffered as a result. In Jammu & Kashmir too, terrorism reared its ugly head. There was trouble in the State ever since 1947. Thousands of young men became victims of

*English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

terrorism. Thousands of people were displaced and had to migrate from Jammu & Kashmir.

Mr Chairman Sir, the present Central Government must play its role to check the menace of terrorism. It must shoulder its responsibility. Illiteracy has to be removed. In the border areas of Punjab, education is a casualty. Scores of posts of school teachers are lying vacant. Students are not getting education due to this. When children are uneducated and illiterate, they are bound to be swayed by the call of gun. In the border areas of Punjab, the landless agriculture workers are facing a lot of problems. They are ploughing the fields but they do not own the land. The poor people want that the land they are ploughing should belong to them. This is only possible if the Central Government passes a law to this effect that the land must belong to the person who ploughs it. Only then can the poor landless agriculturists benefit from it. Mr Chairman Sir, unemployment is another problem. Earlier, the youths of Punjab used to get recruited in army in a big way. But later on, the Central Government passed a law, which restricted the recruitment of Punjabi youths in the Indian army to just 2%. We should do away with such discriminatory rules. Those young men who are physically fit should be recruited in the army. It will reduce unemployment.

Sir, I fully agree with this thesis that after India became independent, the gulf between the rich and the poor has been increasing. The rich have become richer while the poor have become poorer. Until and unless we bridge the divide between the rich and poor, we cannot rein in the menace of terrorism and naxalism. Sir, the need of the hour is to fill this gap between the rich and the poor. Until and unless we do something concrete for the poor farmers and labourers, we cannot check the scourge of terrorism and naxalism. The naxalite movement cannot be crushed only by guns. We must remove the problems and causes that give rise to these movements. We cannot escape these violent movements until we remove their root causes. Sir, we must put our heads together and fulfil the needs of the poor people of the areas where terrorism and naxalism have gained foothold. We will have to use all sources at our command. Only then can we hope to control these movements. Stringent laws should also be framed. The erstwhile

NDA Government had framed POTA but sadly the Congress Government abolished POTA. But we have to be strict in our approach at times. Those who perpetrate mindless violence should be dealt with sternly.

Sir, we the people of India as well as the Government of India want to improve bilateral relations with Pakistan. But the ruling establishment in Pakistan is anti-Indian. It does not want mutual relations to improve. Recently, there was loss of life and property in the earthquake that rattled Pakistan and India. India wanted to help Pakistan in various ways. But Pakistan refused to seek help from India. Now, various points have been opened at line of actual control in Jammu & Kashmir. So, Mr Chairman Sir, we must deal firmly with these anti-national forces.

Sir, in Bihar, naxalites attacked the town and jail of Jehanabad. What are the reasons for it? The problems of the poor people have to be solved. The police force should be strengthened by providing it with modern weapons. Intelligence inputs need to be bolstered. We should not support and encourage such extremist elements just for seeking votes during elections. Only then can we solve these teething problems.

Mr Chairman Sir, during the 1991 elections in Punjab, terrorism was still a force to reckon with. At that time, 27 members of our party were killed by terrorists and elections had to be cancelled. When elections were held again in January 1992, not a single Congress member was killed. Things were under control. So, we must not compromise with terrorists just to gain power in Centre or States. We should not win elections at the cost of lives of members of other political parties. We must fight unitedly against forces that threaten our country. We must take up this issue not only with Pakistan but also with Nepal, Bangladesh and Sri Lanka. Political will is needed to overcome these forces and to solve these problems.

MR. CHAIRMAN : Shri B. Mahtab, you speak only for ten minutes.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Mr. Chairman, Sir, I stand here to participate in the discussion on the Statements on four specific incidents or issues which have been given in this House.

The first issue deals with the bomb blasts which occurred in Delhi on 29th October evening. In fact, there were three bomb blasts on that day. The second issue deals with the terrorist activities which have increased with the change of Government in Jammu & Kashmir. The third issue deals with People's War Group or CPI (Maoist) violence which is spreading its tentacles in different parts of the country. But I am sorry to say that another major terrorist activity centre is in the North East. I think this House will take that up during this Winter Session in due course of time. We have to take the whole nation and view it when we discuss as to what type of terrorists activities are occurring in our country. That has to be discussed specially in this august House. Of course, the House in its wisdom has taken up these three major issues of terrorist activities. I would distinguish these three activities in three different ways. First is the bomb blast in Delhi. It is also a terrorist activity. It is the most heinous type of terrorist activity which does not discriminate any one and which targets a group of people, a large group of people irrespective of their faith, belief, religion, colour and creed. Here, the terrorist mindset is to create terror, to create fear and to create disharmony in the society. This is one type of terrorist activity which is occurring. This group at one point of time was believing in bullets and it was targeting individuals. As was told by my previous speaker, the individuals were targeted and bullets were used. But now bombs are being used. By placing bombs, a large section of population is being targeted and killed so that disharmony occurs in the society; communal violence occurs in the society. That was the major intention. It was just before when the whole country was going to celebrate Diwali, Eid and Gurupurab. This was the basic idea to create disharmony among the communities.

The second type is when we talk of Jammu and Kashmir. They are the group of people who are supported by a larger group who are on the other side of the

borders. They are getting full support. They create module in different parts of the State of Jammu and Kashmir. They create havoc. They target individual people. They barge into Minister's house or MLA's House. They also kill the people. The individuals are being targeted in the Valley and also in Jammu. That is a different type of terrorist activity.

The third aspect is the one which occurred in greed. It is just to loot arms and ammunition from a Home Guard Institute. This occurred on 11th and 13th of November where more than 500 or 600 attacked the district headquarters; or what we saw or what we heard or what we read in the newspapers was that more than thousands of people attacked a district headquarter. They cut down the electricity light and tried to barge into the police line. One naxalite met with an accident there. But the idea was to attack the jail and to free certain Maoists only; not only that but also to capture the Ranvir Sena people and eliminate them. This is a different type of terrorist activity. When we talk of Maoist terrorist activity or the Naxalite or the People's War Group, in the last one and a half years or two, all of them have combined and most of them have been named as CPI(Maoist). We call them the Maoists. It is Maoist terrorism. CPI(Marxist) Party is totally against them. In West Bengal also, they have been targeted.

It was in the news some six months ago. One or two office bearers had been targeted and they had to move away from the place where they were stationed. It had happened in two or three districts in West Bengal. Nobody is free from the clutches of these terrorists. Their tentacles are spreading. That is the greatest danger to the body politic of our nation. I might be allowed a little more time when I go through these three aspects.

I would say that the explosion in Delhi was to create panic by killing people and destroying property. Secondly, it was meant to create ill will among communities and whip up communal passion and also to create confusion in the society. The people at large rose to the occasion and foiled the design. The political leadership of this country, cutting across party lines, rose to the occasion and saw to it that no

political party took mileage from these bomb blasts. That is the greatest thing that this country achieved. It is not only the leaders of the Ruling Party but also the leaders of the Opposition Parties who saw to it that no communal passions were permitted to rise. For all concerned, the utmost priority was to maintain peace and tranquility in this capital city. The common masses who also rose to the occasion saw to it that daily life was restored in the next two or three days. Shops were opened and people came out in large numbers to the streets. That was a fitting reply through which the people could foil the designs of the perpetrators of those terrorist activities.

It is not for the first time that bomb blasts have occurred in Delhi. It had been happening earlier also. As I said earlier, violence as such is an act of cowardice. It exposes the terrorist motives. I would appreciate if the hon. Minister of State for Home Affairs could communicate what I am stating before this House. The hon. Minister of Home Affairs had, on October 31, in a Press statement to the media said: "Do not pressurise to disclose information". The media was pestering the Government to know what type of information the Government had got. Even today, a number of hon. Members have mentioned about this. He was at that time very categorical in saying, 'Do not pressurise to divulge information'. I am not asking the Government to give information now. We do not need information. The country does not need information. What we need is action. We need information on what action has been taken, what is the result and how long it would take to catch the perpetrators of this crime.

We all know that these blasts were timed to create disaffection during a festive season. Diwali was just three days ahead; Eid was following; Gurpurab was just two weeks later; and the International Trade Fair was three weeks later. On these four occasions, people from all over the country came to Delhi and participated. That is why I congratulate the people of this country. Similarly, the

Government also needs to be given credit. I do not deny that. The country has successfully shown that we cannot be cowed down by these types of terrorist activities. At the same time, I should also mention that our national resolve should be to fight terrorism and it must be apparent in our action and policy.

The bomb blasts in Delhi have demonstrated that India is very much in the radar of terrorists. One may say that because we are fighting shoulder to shoulder with United States against Pan-Islamic terrorism, India is being targeted. I do not know whether some hon. Members have said it or not in this House, but this is discussed outside that because we are fighting the Pan-Islamic terrorism shoulder to shoulder along with United States, we are being targeted. I do not subscribe to this view because India has been targeted much earlier, much before United States was targeted by the Pan-Islamic terrorists' organisations. India is an island between two Islamic blocks and India is being targeted by the Pan-Islamic terrorists' organisations. I will just name two. Especially, the entire US bogey which harps on the US thing is without any sense.

Sir, you are very much aware with your experience and your wisdom. Since the French Revolution, terrorism was shown as a useful means for political change. Revolutionaries like Italian Carlo Piscane and thinkers like Karl Marx have also said this. The Russian "Populists" followed by "Anarchists" and "Communists" unleashed a reign of terror which was targeted against a particular class of people but not against commoners. This is history. The world witnessed State-sponsored terrorism in Nazi Germany, in Fascist Italy and Stalinist Russia. But there also the targets were not the whole of people. The most dreaded terrorists network of all time consists of militant Pan-Islamic terrorist group, that is, Al-Qaeda was established by Osama-bin-Laden in 1990. Jaish-e-Mohammed was founded by Maulana Masood Azhar in Pakistan in 2000. There is a number of other Islamic organisations which have cropped up. But all these started when Israel was created and it was a reaction to that. Arms were taken up by a group of people and they wanted to create a situation so that indiscriminate killing can give

them a right to power. That is why, as I have stated earlier, intelligence network has to be increased, investigation capability to be doubly geared up. At the same time, as the time is short, I would only like to make one submission on this aspect. . (*Interruptions*) I have just covered the first aspect. . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You have taken 15 minutes more. Please conclude.

SHRI B. MAHTAB : I will only mention that when such types of disaster strikes, disaster management mechanism should also be put in place. We cannot forget on that eventful evening when scores of people were being brought by ambulances to different hospitals. The doctors, the para-medical staff, the Union Minister of Health, the Union Secretary of Health, Delhi Administration were all geared up to meet that challenge.

We cannot forget that. The whole country saw how our Health Ministry, our medical colleges came forward, and paramedical officers were also there.

MR. CHAIRMAN : Yogi Aditya Nath.

SHRI B. MAHTAB : Sir, please give me some more time.

This type of disaster management activity should also be geared up so that at the time of eventuality, people can get relief and support, and succour. . (*Interruptions*)

Regarding Jammu and Kashmir aspect, I have mentioned. I will come to the last two incidents. Before I come to that, at the same time, I should also mention that during the last six months, naxalite incidents have cropped up in two more districts of Orissa, that is, Sambalpur and Deogarh. More than nine people have been killed. . (*Interruptions*) I will just explain that because hardly the Central Government, the Home Ministry comes to know about the details. Nine people have been killed. One of them was a police personnel. Seven of them were of BPL category. One person had got money and was supported by Indira Awas Yojana. Just because he was unwilling to share a part of that money of Rs. 25,000 with those Maoists, he was killed. The Maoists are envisaging this type of class war. . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Yogi Aditya Nath.

. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You have taken 17 minutes.

. (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : What is the fun in discussing this if I am confined to five or ten minutes? If I am talking irrelevant, then I should be stopped. . (*Interruptions*) Nine districts have been identified as naxalite affected districts in Orissa. In these two districts naxalite movement has cropped up within the last one year. They come under red corridor from Nepal to Tamil Nadu and Karnataka. In these two districts also, general people and common people are being targeted.

At the time when Jehanabad incident occurred, one of the foremost literateure Shrimati Mahasweta Devi came out in support of this type of class struggle. This has actually hurt us to a great extent. This is really unfortunate. I do not deny the manner in which this class struggle or caste struggle is occurring in Bihar. The State failed in Bihar to protect the law. At the same time, mass attack on targeted group had also happened in Jehanabad. A similar thing had occurred in Orissa also last year. In Koraput which is the district headquarters and scores of naxalites from Andhra Pradesh came in to attack, but the police of Orissa could foil that and send them back because of a good Government there. I would only add here . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please conclude. Please help me.

SHRI B. MAHTAB : I understand your constraint, but I would conclude only with these two lines. There is no ideology in this struggle. It is only to extract money to have a parallel system in the society. Even *Palle Sabhas* are being targeted. It happened in different other places. People were looking at Andhra with the hope that some change was going to take place in the last 18 months. However, the situation has gone from bad to worse. The commitment that was given before the election was also withdrawn.

I would conclude by saying that if you do not have a specific policy to deal with this type of terrorist activity, the Indian population will not spare you. One should bear in mind that there is nothing that the people of India punish more strongly than poor governance or soft State.

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री ने पिछले तीन महीनों के अंदर जिन महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के बारे में यहां पर अपनी स्टेटमेंट दी थी, उस पर हम यहां बहस कर रहे हैं। उनमें मुख्य रूप से पिछले चार महीनों के अंदर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी, दीपावली के दो दिन पूर्व दिल्ली के अंदर हुए बम विस्फोट, झारखण्ड के गिरीडीह में नक्सलवादियों ने होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र पर हमला तथा बिहार के जहानाबाद जिला मुख्यालय पर नक्सलवादियों और उग्रवादियों के कब्जे से संबंधित घटनाएं हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को अपनी स्टेटमेंट से अछूता रखा है जैसे असम के अंदर सितम्बर महीने में एक प्रायोजित ढंग से आतंकी हमला हुआ है। पूर्वोत्तर भारत को अलगाव की आग में डालने का प्रयास हो रहा है। उस जातीय हिंसा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है। यही नहीं जम्मू-कश्मीर के अंदर जब वहां पर प्राकृतिक त्रास्दी से लोग पीड़ित थे, उसी समय राज्य के अंदर 12 हिंदुओं का गला रेंत कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस स्टेटमेंट में कहीं भी उस घटना का उल्लेख नहीं है। विभिन्न घटनाओं के बारे में, चाहे वह उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घटना हो या विभिन्न क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हुई हैं जो किसी आतंकवादी और उग्रवादी घटना से कम नहीं हैं, उन सबके बारे में भी चर्चा होनी

चाहिए थी। लेकिन मंत्री जी किन कारणों से वह चर्चा नहीं हो पाई है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बड़ा कष्ट और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस चर्चा का मतलब इस प्रकार से होगा जैसा हमने मानसून सत्र में आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा का हुआ था। जुलाई 5, 2005 को श्री राम जन्म भूमि पर हुए आतंकी हमले और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुए आतंकी हमलों के बारे में उस समय भी चर्चा की थी। उस चर्चा का कोई मतलब नहीं हुआ और जितनी गंभीरता के साथ सरकार ले रही है जैसे सत्ता पक्ष की उपस्थिति और माननीय गृह मंत्री जी की अनुपस्थिति, यह सब इस चर्चा की गंभीरता को स्वयं उजागर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गधे के सिर पर सींग ढूंढ़ने के समान ही इस चर्चा का भी कोई मतलब नहीं होगा।

मैं आपका ध्यान.(व्यवधान) वे गृह राज्य मंत्री हैं। .(व्यवधान)

SHRI S.K. KHARVENTHAN (PALANI): The Minister of State for Home Affairs is sitting here. The Cabinet Minister is in Rajya Sabha. . (*Interruptions*)

YOGI ADITYA NATH : I know that. . (*Interruptions*)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : हम अनुशासन का पालन करते हैं।.(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Yogi Aditya Nath, you continue with your speech. Do not bother about the comments.

. (*Interruptions*)

योगी आदित्यनाथ : पिछले चार महीनों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई हैं, वे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। जब हम आंतरिक सुरक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, तो चार बातें सबके सामने छनकर आती हैं - एक, जिस जम्मू कश्मीर के बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी स्टेटमैंट दी है, उस जम्मू कश्मीर के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित और आईएसआई, जो इसकी खुफिया एजैंसी है, उसके द्वारा पूरे देश के अंदर जिस इस्लामिक आतंकवाद का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, आज लगभग पूरा देश उसकी चपेट में आ गया है। वह एक आतंकवाद है। दो, इस देश के अंदर वह साम्यवादी उग्रवाद है, जिसे आप माओवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में मान सकते हैं। पिछले डेढ़ वर्षों में बहुत तेजी से एक-तिहाई भारत उसकी चपेट में आ गया है। मार्च, 2004 के जो आंकड़े हम सबके पास हैं, उनमें 8 राज्यों के 54 जिलों तक ही सीमित जो नक्सलवाद था, वह पिछले डेढ़ वर्षों में बढ़कर 15 राज्यों के 200 से अधिक जनपदों तक फैला है। उसे जिस तेजी से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिस प्रकार राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे संरक्षण दिया जा रहा है, उसकी गतिविधियों के प्रचार के लिए राजधानी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसके अड्डे स्थापित करवाए जा रहे हैं, उसमें कमी आने की संभावना नहीं है। जहानाबाद की घटना हम सबके सामने एक उदाहरण मात्र है कि लगातार दस घंटे तक जहानाबाद जिला मुख्यालय नक्सलवादियों और उग्रवादियों के कब्जे में रहता है। जहानाबाद बिहार की राजधानी पटना से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। उन उग्रवादियों के खिलाफ एक रणनीति बननी चाहिए थी, वहां सशस्त्र बलों को पहुंचाकर उनका मुकाबला किया जाना चाहिए था, उन्होंने जिस तरह जेल पर

हमला किया, वहां के विभिन्न पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाया, उस दृष्टि से जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। यह साफ उजागर करता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है और साथ-साथ उन तत्वों से राजनीतिक लाभ अर्जित करने की जो तमन्ना भारत के राजनीतिक मानस पटल पर आज भी व्याप्त है, कहीं न कहीं यही कारण है कि हम आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तीन, इस देश के पूर्वोत्तर राज्यों का मामला है। हम कश्मीर की चर्चा करते हैं, देश के विभिन्न भागों में जो बम विस्फोट हुए, जो निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम पूर्वोत्तर राज्यों को भूल रहे हैं। मैंने असम की चर्चा की थी कि वहां सितम्बर में जातीय हिंसा हुई थी। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका कहीं उल्लेख नहीं किया। उसमें सौ से ऊपर लोग मारे गए थे और वह हिंसा कई दिनों तक चलती

रही। उससे पहले 17 जून से जुलाई के अंत तक मणिपुर में नागा उग्रवादी संगठनों ने जो आर्थिक नाकेबंदी की थी, 45 दिनों तक केन्द्र सरकार ने वहां कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की।

इन संवेदनशील मुद्दों पर सरकार कितनी गंभीर है ? पूर्वोत्तर राज्यों की बड़ी अनदेखी की जा रही है। असम के राज्यपाल भारत सरकार को निरन्तर

.(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN : If you are continuing, you can conclude it tomorrow.

योगी आदित्यनाथ : यदि हमें अभी मौका मिले तो हम अपना भाषण खत्म कर देते हैं। .(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, December 2, 2005/Agrahayana 11, 1927 (Saka).